राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

स्वतंत्र प्रभात

जो लिखेगा, वही टिकेगा

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. (UHIN/2009/34814) (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, बुधवार, 08 जुलाई 2026

वर्ष 16, अंक 96, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

यूपी में 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, बिना बताए बढ़ा दिया गया लोड

श्रीलंका की जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प: 25 की मौत, 100 घायल

कृष्ण मोहन राय को मिली मंदिर व्यवस्था की जिम्मेदारी

अयोध्या(एजेंसी)। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, जिसके तहत चंपत राय की विदाई के बाद अब कृष्ण मोहन को ट्रस्ट की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिम्मेदारी संभालते ही कृष्ण मोहन ने अपनी पहली औपचारिक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से ट्रस्ट की साख और जनता के भरोसे को बहाल करने पर जोर दिया। उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि हाल के दिनों में समाज के मन में कुछ बातों को लेकर संशय और अविश्वास का माहौल बना है, जिसे दूर करना ही उनकी सबसे पहली और मुख्य प्राथमिकता होगी।उन्होंने राम भक्तों को भरोसा दिलाया कि इस अविश्वास के भाव को समाप्त करने के लिए जो भी आवश्यक और कड़े कदम उठाने की जरूरत होगी, ट्रस्ट वह सारे कार्य पूरी निष्ठा के साथ करेगा। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि दर्शन के दौरान दर्शनार्थियों द्वारा किए जाने वाले दान को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए एक पुख्ता, पारदर्शी और अभेद्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। बैठक के दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए इस्तीफों पर विस्तृत चर्चा हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता के. परासरन ने ट्रस्ट के संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि इस्तीफा दिए जाने के बाद वह स्वत: प्रभावी माना जाता है और ट्रस्ट के पास इसे

अस्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद दोनों के इस्तीफे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिए गए। हालांकि, ट्रस्ट ने चंपत राय द्वारा वर्षों तक राम मंदिर निर्माण में निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका की सराहना करते हुए उनके अमूल्य योगदान का सम्मान किया। चंपत राय के इस्तीफे के बाद मंदिर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने का दायित्व अंतरिम रूप से कृष्ण मोहन को सौंपा गया है। उन्हें अपनी नई टीम गठित कर सभी व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही ट्रस्ट ने मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है, जिनमें मंदिर से अन्य कीमती वस्तुओं के गायब होने का दावा किया जा रहा था। ट्रस्ट ने साफ किया कि ये बातें पूरी तरह भ्रामक हैं; मंदिर में भेंट स्वरूप प्राप्त लगभग 2,800 प्रकार की सामग्रियों का पूरा रजिस्टर पूरी तरह सुरक्षित है और सभी वस्तुएं अपनी जगह पर हैं।

विमान उतरने से पहले इंडोनेशिया की वायुसेना ने किया एस्कॉर्ट

नई दिल्ली(एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय दौरे पर सोमवार को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच गए। एयरपोर्ट पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। लैंडिंग से पहले इंडोनेशियाई वायुसेना के फाइटर जेट्स ने पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया। यह सम्मान विशेष राजकीय स्वागत का हिस्सा माना जाता है। पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी के किसी देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उनके विमान को एस्कॉर्ट किया जा रहा है। कई बार मेजबान देश की वायुसेना के लड़ाकू विमान उनके विमान को एस्कॉर्ट करते हैं। इसे विशेष

राजकीय सम्मान और स्वागत का प्रतीक माना जाता है। हाल ही में (मई 2026) संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की यात्रा के दौरान देखने को मिला था, जब यूएई वायुसेना के एफ-16 लड़ाकू विमानों ने प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया था। स्वीडन में भी ग्रिपेन फाइटर जेट्स ने विमान को इसी तरह एस्कॉर्ट कर उनका स्वागत किया था।प्रधानमंत्री इंडो पैसिफिक मिशन के तहत 6 दिवसीय विदेश दौरे पर इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों सहित कई अहम विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। पीएम मोदी का यह दौरा भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। यात्रा से पहले पीएम मोदी के बयान में क्या? तीन देशों की यात्रा के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि इसका मकसद इन कीमती विकास साझेदारों के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले समय में हमारे देश के युवाओं को और मौके मिलें। पीएम ने इस यात्रा से जुड़ा एक लेख एक्स पर साझा किया। इंडोनेशिया को लेकर उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति

वायनाड भूस्खलन में चार मौतें

तिरुवनंतपुरम/वायनाड। केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने मंगलवार को वायनाड में हुए भूस्खलन की घटना को लेकर आपातकालीन बैठक की। इस बैठक में राज्य के कृषि मंत्री टी. सिद्दीकी भी शामिल हुए, जो वायनाड से ही हैं। बैठक में अनाक्कम्पॉयिल-कल्लाडी सुरंग सड़क परियोजना के वायनाड छोर पर हुए भूस्खलन की स्थिति और राहत-बचाव कार्यों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही इस भूस्खलन का भयावह वीडियो भी सामने आया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर चलाए जाएं। उन्होंने राजस्व मंत्री ए.पी. अनिल कुमार और कृषि मंत्री टी. सिद्दीकी को तुरंत वायनाड पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान की निगरानी करने के लिए कहा।यह घटना मीनाक्षी पुल के पास कलाड़ी में हुई, जो सुरंग निर्माण स्थल के नजदीक है। निर्माण

स्थल पर खोदी गई मिट्टी का बड़ा ढेर भूस्खलन के दौरान ढह गया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। पिछले 24 घंटों में लगातार हुई भारी बारिश के बाद ढीली मिट्टी धंस गई और नीचे गिर गई, जिससे कार्यस्थल के कुछ हिस्से दब गए।अधिकारियों को संदेह है कि बचाव दल द्वारा खोज जारी रखने के दौरान अभी और अधिक श्रमिक और पर्यटक फंसे हो सकते हैं। यह इलाका पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। भूस्खलन के समय कई निजी वाहन भी वहां आसपास खड़े हुए थे। निर्माण श्रमिकों को परियोजना स्थल तक ले जाने वाली एक बस भी वहां खड़ी थी।

भारत टैक्सी की तर्ज पर शुरू होगी नई सहकारी जीवन बीमा कंपनी: अमित शाह

नई दिल्ली(एजेंसी)। देश के सहकारिता आंदोलन को नया जीवन देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक नीतिगत पहल की है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक भव्य समारोह में घोषणा की कि देश में सहकारी समितियों के विकास को तेज करने के लिए जल्द ही एक नई सहकारी लाइफ इंश्योरेंस (जीवन बीमा) कंपनी का गठन किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि सहकारिता आंदोलन, जो कांग्रेस शासन के दौरान एक उपेक्षित आंदोलन बन चुका था, उसे इस मंत्रालय के गठन से एक महत्वपूर्ण 'लाइफलाइन' मिली है। देश के लगभग 8.5 लाख सहकारिता संगठनों और 30 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए यह

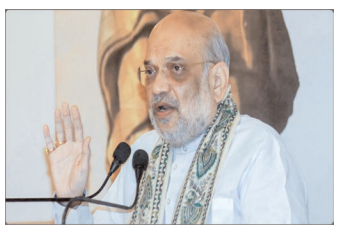

पहल एक दूरगामी गेम-चेंजर साबित होने वाली है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बताया कि देश में सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी का कामकाज बेहद शानदार रहा है और आगामी दो वर्षों में इसका विस्तार 500 शहरों में करने की ठोस तैयारी है।

इसी मॉडल की तर्ज पर, बीमा क्षेत्र में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक स्वतंत्र सहकारी जीवन बीमा कंपनी स्थापित की जाएगी। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि उर्वरक क्षेत्र की दिग्गज सहकारी संस्था इफको (आईएफएफसीओ) पहले से ही एक जापानी फर्म के साथ संयुक्त उद्यम (जॉइंट वेंचर) के जरिए बीमा व्यवसाय में सक्रिय है। यह नई कंपनी सीधे तौर पर सहकारिता क्षेत्र को वित्तीय सुरक्षा के दायरे में लाकर उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेगी। ग्रामीण स्तर पर पैक्स (पीएसीएस) के डिजिटलीकरण और क्षमता निर्माण के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं 50,000 ई-पैक्स (ई-पीएसीएस) का शुभारंभः ग्रामीण स्तर की वित्तीय रीढ़ कही जाने वाली 50,000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) को डिजिटल तकनीक से लैस कर ई-पैक्स (ई-पीएसीएस) में परिवर्तित कर दिया गया है।

भाजपा सरकार कंपनियों की सगी है जनता की नहीं : अखिलेश यादव

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की 'धर्म' और 'धन' दोनों राजनीति का अंत हो गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम गिरने से पेट्रोल-डीजल के दामों में भारी कमी आई है और दूसरे देशों की पब्लिक को तेल के घटे दामों के रूप में लाभ मिला है लेकिन इसके विपरीत भारत में भाजपा सरकार दाम नहीं घटा रही है, कंपनियों को लगातार फायदा पहुँचाने में लगी है। भाजपा सरकार कंपनियों की सगी है जनता की नहीं। अखिलेश यादव ने कहा भारत में तेल या किसी भी चीज के दाम का अपना अनोखा 'भ्रष्ट अर्थशास्त्र' है जो माँग-आपूर्ति से नहीं बल्कि भाजपाई कमीशनखोरी से चलता है, जो कंपनियों के

मुनाफे से जुड़ा है। सामान्य शब्दों में कहें तो कंपनियों का प्रॉफिट-लाभ जितनी ज्यादा होगा, भाजपा को कमीशन भी उतना ज्यादा मिलेगा। इसीलिए हमारे यहाँ हर चीज के दाम बढ़ने महंगाई बढ़ने का कारण भाजपा की कमीशनखोरी है, जिसका खामियाजा आम जनता को महंगे तेल, परिवहन, यातायात, खाद्य पदार्थ व अन्य सभी सामान खरीद कर भुगतना पड़ रहा है। भाजपा के जिन अनभिज्ञ, भोले-भाले समर्थकों को लगता था कि भाजपा ऐसा निकृष्ट कार्य नहीं कर सकती है, मंदिर-चोरी के बाद उनको भी समझ आ गया है कि भाजपाइयों के लिए 'धन' ही 'धर्म' है। अब तो भाजपा और उनके संगी-साथियों को देखकर लोग दरवाजा बंद कर ले रहे हैं। श्री यादव ने कहा कि भाजपा की धर्म की राजनीति का अंत हो गया है, इसीलिए वो अब केवल 'धन' की राजनीति करेगी, इससे भ्रष्टाचार भी बेतहाशा बढ़ेगा और महंगाई भी क्योंकि भाजपा के जिन करोड़ों वोटों में कमी आई है, उन वोटों की कमी को भाजपा पैसे से खरीद कर पूरा करना चाहेगी लेकिन धर्म के नाम पर की गई चोरी के पैसों को कोई नहीं लेना चाहेगा। यही 'अधर्मी भाजपा' की सबसे बड़ी चिंता है। भारत की धर्मभीरू जनता पाप के पैसों की हिस्सेदार नहीं बनेगी। 'चढ़ावा-चंदा-दान' चोरी के खुलने की वजह से भाजपा की 'धर्म' और 'धन' दोनों राजनीति का अंत हो गया है। भाजपा अब कहीं की नहीं रही। जो भाजपा का साथी, वो रामघाती।

तेज गेंदबाज शापूर जादरान का निधन

नई दिल्ली। अफगानिस्तान क्रिकेट को मंगलवार को बड़ा झटका लगा, जब टीम के पूर्व तेज गेंदबाज और देश में क्रिकेट की नींव रखने वाले खिलाड़ियों में शामिल शापूर जादरान का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से एक दुर्लभ और जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की जानकारी साझा करते हुए गहरा शोक व्यक्त किया। शापूर जादरान पिछले जनवरी से भारत के एक अस्पताल में गहन चिकित्सा देखभाल (आईसीयू) में भर्ती थे। पिछले साल अक्टूबर में अफगानिस्तान में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उनके भाई घमई जादरान और पूर्व कप्तान असगर अफगान उन्हें इलाज के लिए भारत लेकर आए थे। जादरान हेमोफैगोसाइटिक लिम्फोहि स्टियो साइटोसिस नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थे।

सूचना निदेशक विशाल सिंह ने पत्रकारों के हित में उठाया अहम कदम

● आयुष्मान कार्ड बनवाना हुआ आसान, पत्रकारों के लिए जल्द शुरू होगा विशेष ऑनलाइन पोर्टल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए सूचना विभाग ने आयुष्मान कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। सूचना निदेशक विशाल सिंह ने बताया कि पत्रकार बंधुओं को आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं तथा शीघ्र ही उनके लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन पत्रकारों ने आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश उनका कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है, वे beneficiary.nha.gov.in पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। यदि पोर्टल पर उनका नाम प्रदर्शित होता है और किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होती है, तो संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक सुधार कराया जा सकता है।

सूचना निदेशक ने कहा कि जिन पत्रकारों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है अथवा आवेदन करने के बावजूद उनका कार्ड नहीं बन पाया है, उनकी सुविधा के लिए सूचना विभाग शीघ्र ही एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से पत्रकार अपने जनपद के जिला सूचना कार्यालय के

अधिकारियों की सहायता से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल के प्रारंभ होने की सूचना सभी संबंधित पत्रकारों को समय से उपलब्ध करा दी जाएगी। इस पहल का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति (पुनर्गठित) के संयोजक प्रभात त्रिपाठी ने सूचना निदेशक विशाल सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए सूचना विभाग लगातार सकारात्मक और प्रभावी प्रयास कर रहा है। उनके अनुसार, विशाल सिंह के नेतृत्व में विभाग की कार्यशैली अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और पत्रकार हितैषी बनी है।

प्रभात त्रिपाठी ने कहा कि सूचना निदेशक के रूप में अपने लगभग एक वर्ष के कार्यकाल में विशाल सिंह ने पत्रकार कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनका लाभ प्रदेशभर के पत्रकारों को मिल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद आयुष्मान कार्ड से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान होगा तथा पत्रकारों को सरकारी सुविधाओं का लाभ अधिक सरलता से प्राप्त हो सकेगा।

एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद दूंगा हर आरोप का जवाब : चंपत राय

अयोध्या(एजेंसी)। राम मंदिर के दानपात्र से चढ़ावा चोरी के मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। ट्रस्ट की बैठक में उनका इस्तीफा स्वीकार किए जाने के एक दिन बाद मंगलवार को उन्होंने रामभक्तों के नाम एक पत्र जारी कर अपनी बात रखी।अपने पत्र में चंपत राय ने कहा कि 7 जून 2026 को राम मंदिर परिसर के दानपात्र की गणना के दौरान हुई चोरी की घटना के बाद तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं और उन पर व्यक्तिगत रूप से अनेक निराधार आरोप

लगाए गए हैं। इसी कारण उन्होंने अब तक मौन धारण किया था।उन्होंने कहा कि 6 जुलाई को हुई ट्रस्ट की बैठक में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो अब सार्वजनिक हो चुकी है। हालांकि यह रिपोर्ट 'परम गोपनीय' थी। उन्होंने रामभक्तों को आश्वस्त करते हुए कहा कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ लगाए जा रहे सभी आरोपों और उठाए गए हर बिंदु पर क्रमवार जवाब देंगे। उनका दावा है कि अंतिम रिपोर्ट के बाद पूरा सच सामने आ जाएगा।पत्र में चंपत राय ने अपने सार्वजनिक जीवन का भी उल्लेख किया। उन्होंने लिखा कि अक्टूबर 1991 में उन्हें संगठन द्वारा अयोध्या भेजा गया था और उनका प्रचारक जीवन 45 वर्षों का रहा है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां उन्होंने कार्य किया, उनका जीवन एक खुली पुस्तक की तरह रहा है। अंत में उन्होंने सभी को आदरपूर्वक नमन किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर रामनगरी के संतों ने मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की। संतों ने कहा कि जो भी निर्णय हुआ, वह परिस्थितियों के अनुरूप उचित है। साथ ही उन्होंने चंपत राय को पूरी तरह निर्दोष बताते हुए कहा कि उनका इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया गया कदम है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। संतों ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सशक्त एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में जो नई व्यवस्था की जा रही है, उसका भी स्वागत है।

संक्षिप्त ख़बरें

दिल्ली में पकड़े गए छह दहशतगर्द

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात 'शहजाद भट्टी नेटवर्क' के दो अलग-अलग मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली और पंजाब के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार, पिस्तौल और खतरनाक पेट्रोल बम (मोलोटोव कॉकटेल) बरामद किए गए हैं। सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी साझा की। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपी दो बेहद खतरनाक और अलग-अलग नेटवर्क के माध्यम से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। इसका सीधा संबंध आतंकी गतिविधियों और देश विरोधी साजिशों से था, जो किसी बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में था। यह पूरी तरह से अवैध हथियारों की तस्करी (आर्म्स स्मगलिंग) में लिप्त था, जो अपराधियों और गैंगस्टरों को हथियारों की सप्लाई करता था।

बिहरोजपुर गंगा घाट पर अवैध बालू खनन का भंडाफोड़, सात पर मुकदमा

गोपीगंज। बिहरोजपुर गंगा घाट पर अवैध बालू खनन व परिवहन के मामले में गोपीगंज पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। छापेमारी के दौरान बालू लदे दो ट्रैक्टर-ट्राली पकड़े गए, जबकि एक चालक मौके से फरार हो गया। खान निरीक्षक की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में जय देवी, राजन कुमार, गोलू, राकेश, अरविंद कुमार, शशिकांत तथा धीरज निशाद को नामजद किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।

हैंडपंप पर पानी भरते समय सर्प ने महिला को काटा

कोंच (जालौन)- घर के बाहर लगे हैंडपंप से पानी भर रही एक बुजुर्ग महिला को सर्प ने काट लिया। उपचार के लिए महिला को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, मोहल्ला जवाहर नगर कोंच निवासी जुवैदा (64) पत्नी इस्माइल शुक्रवार की दोपहर अपने घर के बाहर लगे हैंडपंप से पानी भर रही थी। इसी दौरान अचानक वहां निकले एक सर्प ने उसके हाथ में काट लिया। सांप के काटते ही महिला की हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने समय गंवाए बगैर तत्काल ही जुवैदा को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार किया। फिलहाल महिला की हालत में सुधार बताया जा रहा है।

E25 पेट्रोल लॉन्च होने की खबरें पूरी तरह अफवाह: केंद्र सरकार

नई दिल्ली(एजेंसी)। देश में इथेनॉल-मिश्रित ईंधन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने E25 पेट्रोल के जल्द रोलआउट (लॉन्च) होने वाली खबरों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है। सरकार ने साफ किया है कि भारत में फिलहाल E25 पेट्रोल लाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है और इसे लेकर चल रही खबरें महज अफवाह हैं। यहां इस पूरे मामले को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं:मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बातचीत में स्पष्ट किया है कि E25 पेट्रोल के रोलआउट के दावे 'पूरी तरह से झूठे' हैं। सरकार का कहना है कि किसी भी नीतिगत फैसले से पहले इस ईंधन का व्यापक वैज्ञानिक और तकनीकी मूल्यांकन होना जरूरी है, जो अभी पूरा नहीं हुआ है। एक

सरकारी सूत्र ने सवाल उठाते हुए कहा:जब अभी अलग-अलग गाड़ियों पर E25 ईंधन की टेस्टिंग ही चल रही है, तो इसके रोलआउट का शेड्यूल कैसे तय किया जा सकता है? ' यह स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि सरकार चरणबद्ध तरीके से E25 पेट्रोल पेश कर सकती है। इन खबरों के कारण वाहन मालिकों के बीच इंजन की अनुकूलता और लॉन्ग-टर्म परफॉर्मेंस को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी थीं।

मैं लव मैरिज की विरोधी नहीं : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

लखनऊ(एजेंसी)। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एकेटीयू दीक्षांत समारोह में छात्र-छात्राओं से खुलकर बात की। राजधानी के सिद्धीखेड़ा बालिका गृह की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज कल लड़के-लड़कियां पहले भाग जाते हैं। फिर लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है और ऐसे बच्चे बाद में सरकार के भरोसे हो जाते हैं। उन्हें कोई स्वीकार नहीं करता है और वे बालगृह में पहुंचा दिए जाते हैं। सामने बैठे छात्र-छात्राओं से उन्होंने कहा कि यह आप सबका पराक्रम है। ऐसा पराक्रम न करिए। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भी बंगलौर पढ़ने गया था। मैंने कहा कि कोई लड़की पसंद हो तो बताना, मैं शादी कर दूंगी। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। आपको कोई पसंद आए तो पहले आत्मनिर्भर बनिए, फिर शादी कीजिए। मैं लव मैरिज की विरोधी नहीं हूं।

लेकिन आत्मनिर्भर होने तक शादी न करिए, कुछ गलत न करिए।राज्यपाल ने आंगनबाड़ी, स्कूल-कॉलेजों व विश्व विद्यालयों में हो रहे निर्माण कार्य की डिजाइन व उपयोगिता पर बड़े सवाल खड़े किये। उन्होंने कहा कि यहां होने वाले निर्माण कार्यों को देखकर निराशा होती है। लाइट जलाने का बोर्ड कमरे के बीच में लगा होता है। आंगनबाड़ी में पीने के पानी के टैब इतने ऊंचे हैं कि बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं।ट्यॉलेट इतने ऊंचे हैं कि बच्चे पहुंच नहीं सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी में प्रथम तल पर एक तरफ वीसी, दूसरी तरफ रजिस्ट्रार का कमरा है और बीच में लाइब्रेरी प्रस्तावित की गई है। जबकि छात्रावास वहां से एक किलोमीटर दूर है। उन्होंने इन कमियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि निर्माण वालों की डिग्री फर्जी तो नहीं है।

उन्होंने विवि प्रशासन को कड़े निर्देश दिए कि निर्माण में गुणवत्ता के साथ उपयोगिता का भी ध्यान रखें। निर्देश दिया कि हॉस्टल में मॉर्डन किचन बनाएं, आरओ प्लांट लगवाएं। राज्यपाल ने बताया कि आज मेडल पाने वालों में एकेटीयू के 16, सरकारी कॉलेज के 17 और प्राइवेट के 49 छात्रों को मेडल मिला है। उन्होंने कहा कि सरकारी कॉलेजों में गरीब छात्र पढ़ने जाते हैं। क्योंकि यहां शुल्क कम होता है। अपेक्षाकृत प्राइवेट में ज्यादा फीस देकर पढ़ते हैं। ऐसे में सरकारी स्कूल-कॉलेजों के शिक्षक मेहनत करें। छात्रों को सही से सिखाएं। क्योंकि यहां गरीब के बच्चे आते हैं। इसी तरह प्राइमरी स्कूलों में भी गरीब बच्चे जाते हैं। सरकारी स्कूल-कॉलेजों के शिक्षक पढ़ाई में ध्यान दें। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात का उदाहरण देते हुए सुझाव दिया कि प्रदेश में होने वाले निवेश से जुड़ी जानकारी वाली बुकलेट स्कूल-कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के छात्रों को उपलब्ध कराई जाए। ताकि युवाओं को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने छात्रों से तकनीकी के साथ रचनात्मकता और संस्कृति को बनाए रखने की बात कही। एकेटीयू कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत करते हुए बताया कि एनईपी 2020 लागू करने के साथ ही छात्रों को इंटर डिसीप्लीनरी व माइनर डिग्री भी दी जा रही है।

सम्पादकीय

रील्स के युग में 'लक्ष्मण रेखा' कहां तक

सोशल मीडिया पर आज जिस तरह के कंटेंट देखने को मिल रहे हैं उनको देखकर एक बात मन में तो जरूर उठती है कि इसकी कुछ सीमाएं अति आवश्यक हैं क्योंकि रील मेकर्स व्यूज पाने के लिए अभद्र से अभद्र सामग्री डाल रहे हैं। आजादी ठीक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम समाज को नग्नता परोसें। ऐसा नहीं है कि सरकार इस विषय में कुछ सोच न रही हो लेकिन लोग इसको उनकी आजादी में खलल के हिसाब से देखने लगते हैं। इंस्टाग्राम पर कथित आपत्तिजनक सामग्री को लेकर केन्द्र सरकार ने मेटा पर सख्त रुख अपनाया है। मेटा की टीम ने कल ही इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की है। सरकार ने बीते दिनों इस मामले में तीन दिनों के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है। मेटा ने तय समय-सीमा के भीतर अपना अंतिम जवाब देने का आश्वासन दिया है। इसी बीच सूत्रों के अनुसार केन्द्र सरकार ने इंस्टाग्राम पर बाल योन शोषण से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को बढ़ावा देने वाले कथित विज्ञापनों को भी गंभीरता से लिया है। 30 सेकंड की रील और एक स्वाइप की दूरी। सोशल मीडिया के इस दौर में अभिव्यक्ति की आजादी और अश्लीलता के बीच की लाइन बेहद पतली हो गई है। खासकर इंस्टाग्राम पर, जहां युवा कंटेंट क्रिएटर से लेकर ब्रांड तक सब एक्टिव हैं। ऐसे में सवाल उठता है: आखिर इंस्टाग्राम पर 'अभद्र' माना क्या जाएगा? मेटा की कम्युनिटी गाइडलाइंस का जवाब सीधा है: 'बात कर सकते हो, दिखा नहीं सकते। इंस्टाग्राम की नीति में कुछ मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस है। यहां ढ्ढ भी और यूजर रिपोर्ट भी तुरंत एक्शन लेती है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की किसी भी प्रकार की नग्न या यौन संदर्भ वाली सामग्री। यह केवल प्लेटफॉर्म का नियम नहीं, बल्कि कानूनी अपराध है। बलात्कार, अनाचार, जानवरों के साथ यौन संबंध को महिमामंडित करना या उसका ग्राफिक वर्णन, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। पीली रेखा: 'सेंसिटिव कंटेंट' का दायरा- यह सामग्री प्लेटफॉर्म से हटेगी नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम खुद इसकी पहुंच सीमित कर देगा। यह रील्स टैब एक्सप्लोर और हैशटैग पेज पर दिखाई नहीं देगी। इसमें क्या आता है? बिकनी, पारदर्शी कपड़े, शरीर के अंगों पर फोकस करने वाले वीडियो। सेक्स शिक्षा पर बात करना ठीक है, पर अगर वीडियो में उत्तेजक इशारे या अश्लील ऑडियो जोड़ा गया तो वह इसी श्रेणी में चला जाएगा। हरी रेखा: जो पूरी तरह स्वीकार्य है- रोमांटिक किस, आलिंगन, बॉडी पॉजिटिविटी, सर्जरी के निशान, पीरियड और स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता वाले कंटेंट पर कोई रोक नहीं है। क्यों जरूरी है ये सीमा? साइबर कानून विशेषज्ञ अधिवक्ता प्रांजल शुक्ला कहते हैं, ट्ठ'इंस्टाग्राम पर 13 साल से ऊपर के बच्चे भी हैं। अगर प्लेटफॉर्म पर कोई नियंत्रण न हो तो वह अश्लीलता का अड्डा बन जाएगा। इसलिए मेटा ने ' कोन्टेक्सट इंटेंट और डिस्प्ले' का फॉर्मूला बनाया है।' मतलब: डॉक्टर अगर सेक्स एजुकेशन दे रहा है तो चलेगा। वही बात अगर कॉमेडी के नाम पर भद्दे इशारों से की जाए तो नियम तोड़ेगी। सजा का प्रावधान – नियम तोड़ने पर पहले पोस्ट हटाकर वार्निंग मिलती है। दोबारा करने पर 24 घंटे से 7 दिन तक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट। तीसरी बार में स्थायी बैन। 2024 में Meta ने भारत में ही हजारों अकाउंट अश्लील सामग्री के कारण हटाए थे। क्रिएटर्स के लिए जरूरी बातें- रील्स का कवर फोटो सबसे ज्यादा रिपोर्ट होता है। बैकग्राउंड में चल रहे गाने के बोल अगर अश्लील हैं, तो वीडियो भी येलो जोन में जाएगा। बायो में 18+ वेबसाइट का लिंक डालना सीधे अकाउंट सस्पेंशन का कारण बनता है। डिजिटल इंडिया में इंस्टाग्राम संवाद का बड़ा माध्यम बन चुका है। पर आजादी का मतलब अराजकता नहीं। प्लेटफॉर्म की यही कोशिश है कि वह 'डिजिटल सार्वजनिक स्थान' बना रहे, 'डिजिटल रेड-लाइट एरिया' नहीं।

संपादक/लेखक: राजीव शुक्ला

जल के बिना भी संकट, जल के साथ भी संकट

भारतीय शहर आज विकास की सबसे बड़ी विडंबना का प्रतीक बन चुके हैं। वर्ष का एक हिस्सा पानी की एक-एक बूंद के लिए भटकते हुए गुजरता है, तो दूसरा उसी पानी से बचने के संघर्ष में। कुछ ही महीने पहले दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे महानगरों में सूखे नल, घटता भूजल, टैंकरों के पीछे लंबी कतारें और 'वॉटर क्राइसिस' के बोर्ड दिखाई दे रहे थे। आज वही शहर मूसलाधार बारिश में डूबे हैं। सड़कें नदियों में बदल गई हैं, मेट्रो स्टेशन जलमग्न हैं, वाहन बह रहे हैं और जनजीवन ठप पड़ा है। यह केवल मौसम का उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि उस विकास मॉडल की विफलता है जिसने प्रकृति के साथ चलने के बजाय उसे पराजित करने का भ्रम पाल लिया। सबसे बड़ी चिंता यह है कि जल संकट और जलभराव अब अलग-अलग समस्याएँ नहीं, बल्कि एक ही अव्यवस्थित व्यवस्था के दो चेहरे हैं। गर्मियों में दिल्ली का भूजल खतरनाक स्तर तक गिर जाता है और लोग पानी के लिए भटकते हैं, जबकि मानसून की पहली तेज बारिश में वही इलाके घुटनों तक पानी में डूब जाते हैं। मुंबई में हर वर्ष लोकल ट्रेनें ठप पड़ती हैं और लाखों लोग प्रभावित होते हैं। तकनीकी राजधानी बेंगलुरु में सड़कें जलमग्न होने पर आईटी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम लागू करना पड़ता है। चेन्नई में 2015 की विनाशकारी बाढ़ की यादें आज भी भय पैदा करती हैं। शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में प्रमुख शहरों में जलभराव की घटनाएँ लगभग 35 प्रतिशत बढ़ी हैं। यह केवल वर्षा की तीव्रता नहीं, बल्कि हमारी योजनागत विफलता का प्रमाण है। इस संकट की जड़ें प्रकृति में नहीं, हमारी विकास नीति में हैं। शहरों के अंधाधुंध विस्तार ने झीलों, तालाबों, वेटलैंड्स और प्राकृतिक जलमार्गों को निगल लिया। सदियों तक वर्षा जल सँभालने वाले जलाशयों की जगह मॉल, बहुमंज़िला इमारतें, कॉलोनियाँ और सड़कें खड़ी हो गईं। नतीजतन वर्षा जल के प्राकृतिक निकास मार्ग समाप्त हो गए। बादल अपना काम करते हैं, लेकिन शहर विफल हो जाते हैं। पानी के पास बहने का रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह सड़कों, बेसमेंटों, मेट्रो स्टेशनों और रिहायशी इलाकों में भर जाता है। दिल्ली-एनसीआर का अनेक स्थानों पर 50-60 वर्ष पुराना ड्रेनेज तंत्र आज की आबादी और वर्षा का दबाव नहीं झेल पा रहा, जबकि मुंबई में समुद्र से पुन: प्राप्त भूमि पर जल निकासी और गंभीर हो गई है। प्रकृति को कुचलकर किए गए विकास की कीमत आज हर नागरिक चुका रहा है। स्थिति इसलिए अधिक गंभीर है क्योंकि यह कोई अप्रत्याशित आपदा नहीं। हर वर्ष मानसून आता है, भारी बारिश होती है और जलभराव होता है, फिर भी प्रशासन की तैयारी अधूरी रहती है। नालों की सफाई अधूरी, पंपिंग स्टेशन खराब, ड्रेनेज का आधुनिकीकरण फाइलों में और जल निकासी पर निवेश नाकाफी रहता है। नतीजा, कुछ घंटों की बारिश ही शहर की रफ्तार थाम देती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अनुसार, शहरी बाढ़ से हर वर्ष हजारों करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होता है। इसके बावजूद स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में ड्रेनेज, भूजल पुनर्भरण और वर्षा जल प्रबंधन प्राथमिकता नहीं बन पाए। योजनाएँ आधुनिक दिखती हैं, लेकिन बुनियादी ढाँचा आज भी जर्जर और उपेक्षित है। प्रशासनिक उदासीनता की सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुकाते हैं। कर्मचारी घंटों जाम में फँसते हैं, विद्यार्थी विद्यालय नहीं पहुँच पाते, छोटे व्यापारी कारोबार ठप होने को विवश होते हैं और कई बार गंभीर रोगी समय पर अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते। जलभराव केवल असुविधा नहीं, बल्कि दुर्घटनाओं, संक्रामक रोगों, बिजली संकट और आर्थिक ठहराव का कारण बनता है। दूसरी ओर गर्मियों में यही नागरिक टैंकरों से महँगा पानी खरीदने को मजबूर होते हैं। यानी कुछ ही महीनों में एक ही शहर पानी की कमी और पानी की अधिकता—दोनों का संकट झेलता है। इससे बड़ा विकास का विरोधाभास क्या हो सकता है? स्पष्ट है कि समस्या का समाधान केवल राहत कार्यों से नहीं होगा। भारत को ऐसी समग्र जल नीति चाहिए, जो

> ✦ जल संकट और जलभराव का विरोधाभास - गर्मियों में पानी की कमी, जबकि बरसात में वही पानी बाढ़ और जलभराव का कारण बनता है।
> ✦ विकास मॉडल की विफलता - प्रकृति के अनुरूप विकास न होने से शहर जल संकट और बाढ़ दोनों झेल रहे हैं।
> ✦ प्राकृतिक जल स्रोतों का विनाश - झीलों, तालाबों, वेटलैंड्स और प्राकृतिक जलमार्गों पर निर्माण होने से वर्षा जल का प्राकृतिक निकास बाधित हुआ।
> ✦ पुरानी और कमजोर ड्रेनेज व्यवस्था - अधिकांश शहरों का जल निकासी तंत्र वर्तमान आबादी और भारी वर्षा का सामना करने में सक्षम नहीं है।
> ✦ प्रशासनिक लापरवाही - नालों की समय पर सफाई, पंपिंग स्टेशन और ड्रेनेज आधुनिकीकरण की कमी से हर वर्ष स्थिति बिगड़ती है।

जल संरक्षण, जल निकासी और भूजल पुनर्भरण—तीनों को समान महत्व दे। हर नए निर्माण में वर्षा जल संचयन, पर्मिएबल सड़कें तथा वेटलैंड्स, झीलों और तालाबों का संरक्षण अनिवार्य हो। उपेक्षित पारंपरिक जलाशयों के पुनर्जीवन का राष्ट्रीय अभियान चलाया जाए। दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में वेटलैंड पुनर्स्थापन के सफल मॉडल साबित कर चुके हैं कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और वैज्ञानिक योजना से जल संकट और जलभराव, दोनों पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। अब इन्हें देश की शहरी नीति का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा। समय आ गया है कि शहरों की योजना कंक्रीट नहीं, जल के आधार पर बने। किसी भी सड़क, कॉलोनी, फ्लाईओवर, मेट्रो या आवासीय परियोजना को तभी स्वीकृति मिले, जब वह प्राकृतिक जल प्रवाह में बाधा न बने। शहरी नियोजन का हर निर्णय इस सोच पर आधारित हो कि वर्षा का पानी संकट नहीं, भविष्य की जल सुरक्षा का सबसे बड़ा स्रोत है। वर्षा जल का वैज्ञानिक संचयन, भूजल पुनर्भरण और प्राकृतिक जलमार्गों का पुनर्जीवन सुनिश्चित हो जाए, तो आज का यही पानी कल सबसे बड़ी जीवन-संपदा बन सकता है। भारतीय शहर आज ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ विकास की दिशा बदलना अनिवार्य है। प्रकृति से संघर्ष कर कोई सभ्यता लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकती। जो विकास प्रकृति को मिटाता है, प्रकृति भी उसे टिकने नहीं देती। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई—हर महानगर यही चेतावनी दे रहा है कि अभी भी समय है। यदि जल-संवेदनशील शहरी नियोजन, उत्तरदायी प्रशासन और प्रभावी जल नीति को तुरंत लागू नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में शहर हर मानसून में डूबेंगे और हर गर्मी में प्यासे रहेंगे। तब इतिहास यही दर्ज करेगा कि हमने पानी को संसाधन नहीं, संकट बना दिया—और यही हमारे विकास मॉडल की सबसे बड़ी विडंबना होगी।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

प्रदेश के सभी जिलों में 'हुनर से आत्मनिर्भरता' का महा-अभियान

प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने तथा युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 'एक जनपद-एक उत्पाद' योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपदों में व्यापक कौशल विकास अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से कुल 8,525 युवाओं को उनके जिले के प्रमुख पारंपरिक उत्पादों से जुड़े आधुनिक एवं उद्योगोन्मुखी कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की यह पहल स्थानीय उत्पादों को आधुनिक तकनीक, डिजाइन, गुणवत्ता, पैकेजिंग एवं डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ते हुए उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार तथा स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे और स्थानीय उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश का हर जिला किसी न किसी खास हुनर और उत्पाद के लिए जाना जाता है। कहीं की साड़ी, कहीं का इत्र, कहीं का ताला तो कहीं का फर्नीचर। लेकिन बदलते समय के साथ ग्राहक की पसंद, डिजाइन और क्वालिटी के मानक भी बदल गए हैं। ऐसे में पारंपरिक कारीगरी को आधुनिक कौशल से जोड़ना जरूरी हो गया है। उ0प्र0 कौशल विकास मिशन का यह अभियान इसी जरूरत को पूरा कर रहा है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को दो चरणों में लागू किया है। प्रथम चरण का शुभारंभ 1 अप्रैल 2026 से किया गया, जिसमें प्रदेश के 17 जनपदों के 1,050 युवाओं को 'एक जनपद एक उत्पाद' आधारित विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रथम चरण की सफलता तथा युवाओं की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए अब अभियान का विस्तार करते हुए दूसरे चरण में शेष 58 जनपदों के 7,475 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोनों चरणों को मिलाकर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कुल 8,525 युवाओं को उनके जिले के प्रमुख एक जनपद एक उत्पाद के उत्पादों के निर्माण, डिजाइनिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग एवं उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पूरी तरह नि:शुल्क है और चयनित युवाओं को प्रशिक्षण अवधि में स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। कौशल विकास मिशन द्वारा प्रत्येक जिले के प्रमुख पारंपरिक उत्पाद एवं उद्योग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। इन मॉड्यूल को तैयार करने में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आईआईटी कानपुर के इनक्यूबेशन सेंटर और स्थानीय एक्सपोर्ट हाउस की मदद ली गई है। प्रशिक्षण का फोकस केवल 'उत्पाद बनाना' सिखाने पर नहीं है, बल्कि 'उत्पाद बेचना' और 'ब्रांड बनाना' सिखाने पर भी है। हर कोर्स में डिजाइन इनोवेशन, लागत घटाना, जीरो डिफेक्ट प्रोडक्शन, आकर्षक पैकेजिंग, ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग को शामिल किया गया है। प्रथम चरण में एटा में 575 युवाओं को हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां पीतल के पारंपरिक घंटों और सजावटी सामान को अब कंटेम्परेरी होम डेकोर के हिसाब से बनाया जा रहा है। युवाओं को लेजर कटिंग मशीन, पाउडर कोटिंग, एंटीकफिनिश और अमेजन ग्लोबल सेलिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। मिर्जापुर में 200 युवाओं को कालीन एवं हैंडीक्राफ्ट में डिजिटल लूम चलाना, ऑटो-कैड पर डिजाइन बनाना, नेचुरल डाई का इस्तेमाल और यूरोपीय देशों के सेफ्टीनॉर्म्स सिखाए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में 350 तथा बहराइच में 300 युवाओं को फूड प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण मिल रहा है। इसमें आंवला कैंडी, शहद, अचार, रेडी-टू-ईट खिचड़ी और मिलेट बेस्ड स्नैक्स को एफएसएसएआई मानकों के अनुसार बनाना, वैक्यूम पैकेजिंग, न्यूट्रिशन लेबलिंग और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचना शामिल है। गौतमबुद्ध नगर में 200 युवाओं को अपैरल एवं फैशनडिजाइनिंग में डिजिटल फैब्रिक प्रिंटिंग, 3डी सैंपलिंग, बायरकम्युनिकेशन और सस्टेनेबलफैशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। आगरा में 75 युवाओं को आधुनिक लेदरटेक्नोलॉजी में इटालियनफिनिशिंग, लेजरइंग्रेविंग, आरईएसीएच कंप्लायंस और प्राइवेट लेबलिंग की जानकारी दी जा रही है। दूसरे चरण में वाराणसी के 200 युवाओं को आधुनिक टेक्सटाइल एवं डिजाइनिंग में बनारसी साड़ी को डिजिटल जैक्वार्ड पर बुनना, जीआई टैग का सही इस्तेमाल, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट से इंटरनेशनल कस्टमर तक पहुंचना सिखाया जाएगा। गोंडा के 250 युवाओं को दलहन आधारित फूडप्रोसेसिंग में पैकेज्ड दाल, बेसन, सत्तू, प्रोटीन बार बनाना और होटल-रेस्तरां चेन को बी2बी सप्लाई करना सिखाया जाएगा। महाराजगंज एवं पीलीभीत के 500 युवाओं को आधुनिक फर्नीचर एवं वुडन फिटिंग निर्माण में सीएनसी मशीन ऑपरेशन, फ्लैट-पैक फर्नीचर डिजाइन, नॉक-डाउन फिटिंग और डी2सी ब्रांड बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अन्य जनपदों में भी उनके प्रमुख उत्पादों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। लखनऊ की चिकनकारी को लक्जरी फैशन ब्रांडिंग, कानपुर के लेदर गुड्स को वेजिटेबल टैनिंग और यूरोपीय एक्सपोर्ट, फिरोजाबाद के कांच को मॉडर्न लाइटिंग और आर्ट इंस्टालेशन, मुरादाबाद के पीतल को 3डी प्रिंटेड मोल्ड और कंटेनर शिपमेंट, सहारनपुर की लकड़ी नक्काशी को स्कैंडिनेवियन डिजाइन, भदोही की कालीन को कस्टम साइज और वॉल-टू-वॉल कारपेट, कन्नौज के इत्र को अल्कोहल-फ्री अत्तर और गल्फ मार्केट, अलीगढ़ के ताले को स्मार्ट लॉक और बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में केवल पारंपरिक उत्पादन तकनीकों तक ही प्रशिक्षण सीमित नहीं रहेगा, बल्कि युवाओं को आधुनिक मशीनों का संचालन, गुणवत्ता प्रबंधन, आकर्षक पैकेजिंग, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, उद्यमिता विकास तथा उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप भी प्रशिक्षित किया जाएगा। हर बैच को 'कैपस्टोन प्रोजेक्ट' करना होगा, जिसमें वे अपने प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप, कॉस्ट शीट, पैकेजिंग डिजाइन और 30 सेकंड की रील बनाकर जमा करेंगे। बेस्ट तीन प्रोजेक्ट को 'ओडीओपी इनोवेशन अवॉर्ड' के साथ 5 लाख रुपये तक की सीडमनी दी जाएगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद युवाओं को प्रतिष्ठित उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं, बैंक ऋण एवं मुद्रा योजना सहित अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। कौशल विकास मिशन ने सिडबी, नाबार्ड, जिला उद्योग केंद्र और प्रमुख बैंकों के साथ मिलकर 'क्रेडिट प्लस स्किल' मॉडल बनाया है। इसके तहत ट्रेनिंग पूरी करने वाले युवा को 24 घंटे में लोन अप्रूवल की सुविधा मिलेगी। हर जिले में ओडीओपी रोजगार मेला लगेगा, जिसमें फ्लिपकार्ट समर्थ, अमेजनकरिगर, रिलायंस रिटेल, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जैसी संस्थाएं हिस्सा लेंगी। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने प्रशिक्षण प्रक्रिया को पूर्णत: डिजिटल एवं पारदर्शी बनाया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी मिशन की आधिकारिक वेबसाइट नचेकउण्हवअण्पद पर जाकर ओडीओपी लिंक के माध्यम से अपने जिले के प्रशिक्षण केंद्र, उपलब्ध ट्रेड, प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान तथा आवेदन संबंधी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर क्लास रूम में बायोमेट्रिक अटेंडेंस, सीसीटीवी लाइव स्ट्रीमिंग और एआई बेस्डअसेसमेंट होगा। पास होने वाले युवाओं को स्किल इंडिया डिजिटल वॉलेट में एनसीवीईटी सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसे क्यू.आर कोड से वेरिफाई किया जा सकेगा। यह अभियान 'हुनर से आत्मनिर्भरता' को सिर्फ नारा नहीं, बल्कि जमीन पर उतरता हुआ मॉडल बना रहा है। जब हर जिले का युवा अपने हुनर से कमाएगा और हर जिले का उत्पाद दुनिया के बाजार में बिकेगा, तभी उत्तर प्रदेश सही मायने में 'उद्यम प्रदेश' बनेगा।

धर्मवीर खरे

समुद्र से हो सकता है पेयजल मंथन

देश के अनेक शहरों और गांवों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। नदियां प्रदूषित हो रही हैं, वर्षा का स्वरूप अनिश्चित होता जा रहा है और जलवायु परिवर्तन ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। बढ़ती आबादी, तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। तीन ओर से समुद्र से घिरे भारत के सामने जल का असीमित भंडार मौजूद है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97 प्रतिशत भाग समुद्रों में खारे पानी के रूप में है, जबकि केवल लगभग 2.5 प्रतिशत जल मीठा है। इसमें भी अधिकांश जल हिमनदों और बर्फ की चादरों में बंद है तथा मानव उपयोग के लिए सीधे उपलब्ध मीठा जल एक प्रतिशत से भी कम है। ऐसे में समुद्री जल को शुद्ध कर उपयोग योग्य बनाना भविष्य की आवश्यकता बनता जा रहा है।आज आधुनिक विज्ञान की सहायता से समुद्री जल से नमक और अन्य अशुद्धियां हटाकर उसे पेयजल में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे समुद्री जल शोधन कहा जाता है। विश्व के अनेक देशों ने इसे अपनी जल सुरक्षा की आधारशिला बना लिया है। भारत के लिए भी अब इस दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ने का समय आ गया है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान जैसे देशों में प्राकृतिक मीठे जल के स्रोत अत्यंत सीमित हैं। वहां वर्षा नगण्य होती है और अधिकांश भूभाग रेगिस्तान है। इसके बावजूद वहां नागरिकों को चौबीसों घंटे सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। इसका मुख्य कारण समुद्री जल शोधन संयंत्र हैं। भारत की स्थिति खाड़ी देशों से अलग अवश्य है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। विश्व की लगभग 18 प्रतिशत आबादी भारत में रहती है, जबकि मीठे जल संसाधनों में उसकी हिस्सेदारी केवल लगभग 4 प्रतिशत है। देश में उपलब्ध मीठे जल का लगभग 80 प्रतिशत उपयोग कृषि क्षेत्र करता है। दूसरी ओर, उद्योगों और शहरों की बढ़ती आवश्यकताओं ने जल संकट को और गहरा कर दिया है। सबसे बड़ी चिंता भूजल का लगातार दोहन है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु सहित अनेक राज्यों में भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। कई क्षेत्रों में हर वर्ष लगभग एक मीटर तक जल स्तर गिरने की रिपोर्ट सामने आती रही है।

मुख्यमंत्री आवास योजना से फिरोजाबाद में संवर रहे वंचितों के आशियाने

उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार अंत्योदय के अपने मूल संकल्प को धरातल पर उतारते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सभी प्रमुख सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी संवेदनशीलता के साथ पहुंचा रही है। राज्य सरकार की इस लोक-कल्याणकारी नीति का सबसे प्रभावी और जीवंत रूप फिरोजाबाद जनपद में देखने को मिल रहा है, जहां विकास की मुख्यधारा से कटे और उपेक्षित परिवारों के जीवन में 'मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' खुशहाली का एक नया सवेरा लेकर आई है। विशेष रूप से जनपद के शिकोहाबाद विकास खंड की ग्राम पंचायत असुआ की रहने वाली माया देवी की कहानी शासन के इसी संकल्प की एक जीवंत और अनुपम मिसाल है। पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद दुख में डूबी माया देवी के लिए यह योजना एक नई रोशनी बनकर आई, जिसने न केवल उनके सिर पर सुरक्षित छत दी, बल्कि उनके बच्चों के भविष्य को भी पूरी तरह सुरक्षित किया। पति के निधन के बाद माया देवी के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। दो छोटे बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी और रहने के लिए कोई पक्का मकान न होना उनकी सबसे बड़ी व्यथा थी। वे अपने परिवार के साथ तिरपाल से बनी एक अत्यंत जर्जर और कच्ची झुग्गी में रहने को मजबूर थीं। बारिश और हाड़ कंपाने वाली ठंड के मौसम में ऐसी कच्ची झुग्गी में समय काटना किसी भयानक चुनौती से कम नहीं था, साथ ही उन्हें हमेशा अपने और बच्चों की सुरक्षा का डर सताता रहता था। जब माया देवी को जानकारी हुई कि प्रदेश सरकार विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को विशेष प्राथमिकता के आधार पर आवास मुहैया करा रही है, तो उन्होंने आवेदन किया। पात्रता सर्वे के दौरान प्रशासन द्वारा उन्हें उपयुक्त पाया गया और योजना के तहत उनके आवास की स्वीकृति मिल गई। सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए ?1 लाख 20 हजार की कुल राशि तीन किस्तों (?40 हजार, ?70 हजार और ?10 हजार) में सीधे उनके खाते में भेजी गई। पारदर्शिता की दृष्टि से इस संपूर्ण सहायता राशि को बिचौलियों के हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। 'आवास सॉफ्ट' जैसे अत्याधुनिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और त्वरित भौतिक सत्यापन करने के उपरांत यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' के माध्यम से निर्माण कार्य की प्रगति के अनुरूप भेजी जाती है, जिससे सरकारी धन का शत-प्रतिशत सदुपयोग केवल और केवल एक सुदृढ़ मकान के निर्माण में ही सुनिश्चित हो रहा है। प्रदेश सरकार ने संवेदनशीलता के साथ विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं का आपसी समन्वय (कन्वर्जेंस) करके लाभार्थियों को बहुआयामी आर्थिक संबल दिया। इसी कल्याणकारी कड़ी में, माया देवी को आवास निर्माण के साथ-साथ 90 दिन की मनरेगा मजदूरी के रूप में ?22,680 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। इस दोहरे एवं दूरगामी सहयोग ने उन्हें आर्थिक रूप से टूटने से बचा लिया और वह पूरे सम्मान के साथ अपना घर बना सकीं। इसके साथ ही, उन्हें 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत नि:शुल्क गैस कनेक्शन से भी लाभान्वित किया गया, जिसने उन्हें धुएं से मुक्ति और स्वच्छ ईंधन का उपहार दिया। आज माया देवी का पक्का मकान पूरी तरह बनकर तैयार है, जहां वे अपने बच्चों के साथ पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती हैं और एक खुशहाल जीवन जी रही हैं। इस घर ने उनके बच्चों को शिक्षा के लिए एक बेहतर माहौल दिया है, जिससे उनके जीवन में एक सुनहरे भविष्य की शुरुआत हुई है। माया देवी जैसी पात्र महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर आवास, उज्ज्वला योजना और मनरेगा मजदूरी का सामूहिक लाभ देकर समाज के सबसे वंचित और जरूरतमंद वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ना ही शासन का मुख्य उद्देश्य है। शासन के स्पष्ट निर्देशानुसार प्रशासन का निरंतर यही प्रयास है कि जनपद में कोई भी पात्र व्यक्ति आवास विहीन न रहे। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन को इस पूरी योजना का सबसे मजबूत स्तंभ बनाया गया है। आवेदनों की बारीकी से जांच और चयन प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा महिलाओं, विशेषकर विधवाओं, एकल माताओं और महिला प्रधान परिवारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

मेष –मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और उत्साह से भरपूर रहने वाला है। कार्यस्थल पर आपकी योग्यता की सराहना हो सकती है और जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ सम्मान भी प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी तथा परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा।

वृषभ–वृषभ राशि के जातकों के लिए आज पारिवारिक जीवन सुखद रहने की संभावना है। घर की आवश्यकताओं और सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन इससे संतुष्टि का अनुभव होगा।

मिथुन –मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला रहेगा। आपकी वाणी और व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे, जिससे नए संपर्क बनने की संभावना है।

कर्क–कर्क राशि के जातकों के लिए आज आर्थिक मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं। लंबे समय से अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। परिवार में आपसी सामंजस्य बना रहेगा और घरेलू वातावरण सुखद रहेगा।

सिंह –सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रभावशाली रहने वाला है। आपका आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। नौकरी और व्यापार में आपकी छवि मजबूत होगी।

कन्या –कन्या राशि के जातकों को आज अपने खर्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। दूर स्थानों या विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। मानसिक रूप से आप पहले की तुलना में अधिक शांत महसूस करेंगे।

तुला–तुला राशि के जातकों के लिए आज आय और लाभ के नए अवसर बन सकते हैं। मित्रों तथा वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलने से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। व्यापार में लाभ बढ़ने की संभावना है। पुराने निवेश से भी अच्छा प्रतिफल मिल सकता है। प्रेम संबंधों में विश्वास और सामंजस्य बना रहेगा।

वृश्चिक –वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होगी। व्यापार में नई साझेदारी या महत्वपूर्ण समझौता होने की संभावना है।

धनु –धनु राशि के जातकों के लिए आज भाग्य का पूरा साथ मिलने की संभावना है। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर से जुड़े प्रयासों में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं।

मकर –मकर राशि के जातकों को आज निवेश और साझेदारी से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए। अचानक आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और परिवार का सहयोग मिलेगा। **कुंभ** –कुंभ राशि के जातकों के लिए आज संबंधों को मजबूत करने वाला दिन रहेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और आपसी विश्वास मजबूत होगा। व्यापारिक साझेदारी से लाभ मिलने के संकेत हैं।

मीन –मीन राशि के जातकों के लिए आज मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर रहेगा। दैनिक कार्य समय पर पूरे होंगे तथा आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं।

सिर्फ सजावट नहीं, सेहत का भी ख्याल रखता है स्नेक प्लांट

आजकल लोग अपने घरों और कार्यालयों को हरा-भरा और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के इनडोर पौधे लगाते हैं। इन्हीं में से एक है स्नेक प्लांट (संसेविएरिया), जो अपनी खूबसूरत लंबी पत्तियों के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी कई लाभों के लिए भी जाना जाता है। यह ऐसा पौधा है जो कम देखभाल में आसानी से बढ़ता है और घर के वातावरण को बेहतर बनाने में मदद करता है। स्नेक प्लांट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हवा को शुद्ध करने में सहायक माना जाता है। यह वातावरण में मौजूद कुछ हानिकारक तत्वों जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन और ट्राइक्लोरोएथिलीन जैसे प्रदूषकों के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। यही कारण है कि इसे घर, कार्यालय और अन्य

इनडोर स्थानों के लिए एक लोकप्रिय पौधा माना जाता है। इस पौधे की एक और खास बात यह है कि यह रात के समय भी ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे नींद अच्छी आती है और हवा शुद्ध रहती है। यह हवा में मौजूद टॉक्सिन्स जैसे फार्मेल्डिहाइड, बेंजीन और ट्राइक्लोरोएथिलीन को कम करता है। इसी वजह से कई लोग इसे बेडरूम में रखना पसंद करते हैं। स्नेक प्लांट मानसिक सुकून देने में भी मददगार माना जाता है। घर या कार्यस्थल पर हरियाली का होना तनाव कम करने और सकारात्मक माहौल बनाने में सहायक हो सकता है। इसकी सादगी और आकर्षक बनावट कमरे की सुंदरता बढ़ाने के साथ मन को भी ताजगी का एहसास कराती है।

यदि आप ऐसे पौधे की तलाश में हैं जिसकी देखभाल आसान हो तो स्नेक प्लांट एक अच्छा विकल्प है। इसे बार-बार पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। सामान्यत: सप्ताह में एक बार या मिट्टी पूरी तरह सूखने पर ही पानी देना पर्याप्त रहता है। अधिक पानी देने से इसकी जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। यह अप्रत्यक्ष धूप या हल्की रोशनी में भी अच्छी तरह बढ़ता है, इसलिए व्यस्त जीवनशैली वाले लोगों के लिए यह उपयुक्त पौधा है।

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। नोट:-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2009/34814 मो0 नं0 -9511151254, E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

यूपी में 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, बिना बताए बढ़ा दिया गया लोड

लखनऊ(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में पॉवर कॉरपोरेशन की ओर से बिना सूचना दिए लगभग 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं का स्वीकृत भार बढ़ा देने से करीब 25 फीसदी गरीब उपभोक्ता सब्सिडी योजना से बाहर हो गए हैं। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस पर आपत्ति जताई है। पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बढ़ाए गए भार वाले उपभोक्ताओं में करीब 50 फीसदी स्मार्ट मीटर धारक हैं। इनमें से करीब 25 फीसदी ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्हें रियायती दरों पर बिजली मिलती थी। लेकिन भार बढ़ा देने से इन गरीब उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी स्वतः समाप्त हो गई है। ऐसे में ग्रामीण इलाके के गरीबी रेखा के नीचे वाले उपभोक्ताओं पर प्रतिमाह औसतन 165 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं, शहरी गरीब उपभोक्ताओं को प्रतिमाह लगभग 435 रुपये अधिक चुकाने होंगे। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि यह कदम विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश के विपरीत है। टैरिफ आदेश में साफ है कि उपभोक्ताओं का तीन माह तक अधिक भार होने पर उसे सूचना दी जाएगी। इसके बाद उपभोक्ताओं को संदेश भेजकर यह बताना होगा कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपने स्वीकृत लोड से अधिक भार का उपयोग किया। ऐसे में स्वीकृत लोड एक किलोवाट को बढ़ाकर दो किलोवाट किया जा रहा है। बिना सूचना दिए स्वीकृत भार बढ़ाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। वर्मा ने राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने भविष्य में टैरिफ आदेश और नियामकीय प्रावधानों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने की भी मांग।

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर दोहरी मार वर्मा ने बताया कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद विद्युत उपभोक्ताओं से अधिकतम मांग जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। इसके बाद भी प्रदेश में यह वसूला जा रहा है। जुर्माना लेने के साथ ही उनका स्वीकृत भार भी बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर दोहरी मार पड़ रही है।प्रदेश में करीब 1.70 लाख बीपीएल उपभोक्ता हैं। एक किलोवाट पर 50 रुपया फिक्स्ड चार्ज है। इन्हें करीब 300 रुपये का भुगतान करना होता है। अब जिन उपभोक्ताओं का भार बढ़ाकर दो किलोवाट कर दिया गया है तो उनका 180 रुपया फिक्स्ड चार्ज के साथ अधिक ऊर्जा शुल्क देना पड़ेगा। ऐसे में ग्रामीण उपभोक्ता को करीब 165 प्रतिमाह का अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा।

सराय नदी किनारे रिवर फ्रंट पार्क बनाने की उठायी मांग

हरिओम राजेंद्र बोले यह सिर्फ पार्क नहीं, शहर की नई पहचान बनेगा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। शहर के बीचों-बीच बहने वाली सराय नदी के किनारे कैंची पुल से लेकर उजागर लाल इंटर कॉलेज स्थित पक्का पुल तक फैले वन क्षेत्र को 'सराय रिवर फ्रंट एवं पार्क' के रूप में विकसित किए, जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाने वाले लोक निर्माण संघ के संस्थापक हरिओम मिश्रा 'राजेंद्र' ने इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव रखते हुए कहा है कि यदि इस क्षेत्र को सुनियोजित ढंग से विकसित किया जाए तो यह न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाएगा, बल्कि हजारों लोगों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक जीवन के लिए भी वरदान साबित होगा। हरिओम राजेंद्र का कहना है कि वर्तमान में सुबह और शाम बड़ी संख्या में बुजुर्ग, युवा और महिलाएं टहलने के लिए कैंची पुल तक पहुंचते हैं। लेकिन वहां बैठने, विश्राम करने या सुरक्षित भ्रमण के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। यदि नदी किनारे हरियाली को संरक्षित रखते हुए वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम, बैठने की व्यवस्था, बच्चों के खेलने का क्षेत्र और आकर्षक रिवर फ्रंट विकसित किया जाए, तो यह स्थान शहरवासियों के लिए स्वास्थ्य और सुकून का केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बुजुर्गों को स्वच्छ वातावरण और नियमित सैर की सबसे अधिक आवश्यकता है। दूसरी ओर मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में उलझी युवा पीढ़ी को प्रकृति से जोड़ने के लिए ऐसे सार्वजनिक स्थलों का विकास बेहद जरूरी है। बच्चों को भी खुला और सुरक्षित वातावरण मिलेगा, जहां वे खेल सकेंगे और प्रकृति के बीच समय बिता सकेंगे। हरिओम राजेंद्र ने कहा कि यह परियोजना केवल सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन, सामाजिक सहभागिता और जनस्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। उनका मानना है कि यदि शासन-प्रशासन इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करे तो यह स्थल प्रधानमंत्री 'विकसित भारत' की परिकल्पना के अनुरूप सीतापुर की पहचान बन सकता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से इस महत्वाकांक्षी परियोजना को प्राथमिकता देने की अपील करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुंदर और हरित शहर देना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि यह सपना साकार होता है तो सराय नदी का यह किनारा केवल एक पार्क नहीं, बल्कि सीतापुर की नई पहचान और लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का केंद्र बनेगा।

धूमधाम से सम्पन्न हुआ विदाई समारोह, कौशलेन्द्र सिंह बने मिस्टर फेयरवेल व यासमीन बानो बनीं मिस फेयरवेल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

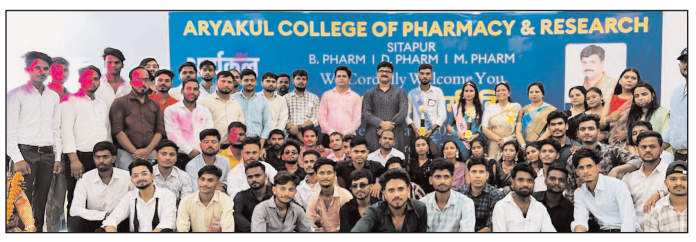

सीतापुर। आर्य इति 2025-26 के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के सम्मान में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, मनोरंजक गतिविधियों एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान मिस्टर फेयरवेल का खिताब कौशलेन्द्र सिंह तथा मिस फेयरवेल का खिताब यासमीन बानो को प्रदान किया गया। विजेताओं को स्मृति चिन्ह एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रबन्ध निदेशक डॉ. सशक्त सिंह ने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने और संस्थान का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्या डॉ. स्तुति वर्मा ने विद्यार्थियों को उनके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं। डीन अकादमिक श्रीमती रुचि सिंह, उपनिदेशक डॉ. आदित्य सिंह तथा डॉ. अब्दुल रब खान ने भी विद्यार्थियों को सफलता के लिए प्रेरणादायक संदेश दिए। समारोह में रजिस्ट्रार रोहित सिंह, अध्यापक राजीव कुमार, ऋषभ शुक्ल, तबस्सुम बानो, अनुभा धुरिया, तान्या, मोहित यादव, रेहान, साहिल सिंह तथा स्टाफ सदस्य अरुण सिंह, प्रवीण यादव, प्रीति यादव, प्रीति तिवारी, अबरार अली, तिलक राज, रमा सिंह, आदर्श सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन वरिष्ठ विद्यार्थियों की भावुक विदाई, स्मृति-चिन्ह वितरण एवं समूह छायाचित्र के साथ हुआ। पूरे समारोह में उत्साह, उल्लास और भावनात्मक वातावरण देखने को मिला।

यूपी की कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल, युवाओं और बहुजन समाज के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा शनिवार को राजधानी लखनऊ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध और अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं तथा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम का सख्ती से पालन कराया जाए और पीड़ितों को समय पर न्याय एवं सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। विनय रतन सिंह ने युवाओं के भविष्य को लेकर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में लंबित सरकारी भर्तियों को शीघ्र पूरा किया जाए तथा भर्ती परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों और छात्रावासों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा प्रतियोगी छात्रों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों और सार्वजनिक भवनों का नियमित सुरक्षा एवं फायर ऑडिट कराया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। साथ ही प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मजबूत कर प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। प्रेस वार्ता में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार, युवाओं के लिए रोजगार एवं कौशल विकास के अवसर बढ़ाने तथा संविधान की मूल भावना–समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व–के अनुरूप शासन व्यवस्था लागू करने की भी मांग की गई। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनकी मांगें किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं, बहुजन समाज और आम नागरिकों के हित में उठाई जा रही हैं। उन्होंने सरकार से जनहित के इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कदम उठाने की अपील की।

कोठार में सुरक्षित है रामचरितमानस की स्वर्णयुक्त प्रति

अयोध्या(एजेंसी)। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि लगभग दो वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी लक्ष्मीनारायण की ओर से भेंट की गई सोने से युक्त श्रीरामचरितमानस सुरक्षित है। पूर्व आईएएस ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू में आशंका जताई थी कि करीब 5 करोड़ की लागत से निर्मित सोने की रामायण जो उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट की थी, वह भी चोरी हो गई है। इसके बाद रविवार को राम मंदिर निर्माण सहायक गोपाल राव ने जानकारी दी कि दानदाता की इच्छा के अनुरूप इसे पहले श्रीरामलला के गर्भगृह के सामने सम्मानपूर्वक रखा गया था। इसके बाद निर्धारित व्यवस्था के तहत रामचरितमानस को मंदिर के गूढ़ मंडप स्थित आभूषण कोठरी में सुरक्षित रख दिया गया। यह भेंट मंदिर के दान रजिस्टर में उसी समय दर्ज की गई थी। कहा कि श्री लक्ष्मीनारायण जब भी चाहें मंदिर आकर अपनी भेंट को देख सकते हैं। रामचरितमानस पूरी तरह सुरक्षित है और उसके संबंध में किसी प्रकार की आशंका की आवश्यकता नहीं है। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सोमवार को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से एक दिन पहले अयोध्या में पूरे दिन हलचल बनी रही। मठ-मंदिरों, संतों के आश्रमों, ट्रस्ट से जुड़े लोगों और रामभक्तों के बीच बैठक को लेकर चर्चाओं का दौर चलता रहा। राम मंदिर दान प्रकरण और एसआईटी जांच के बीच होने जा रही इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। बैठक से ठीक एक दिन पहले ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास अचानक अयोध्या से बाहर चले गए। महंत दिनेंद्र दास ने बताया कि वे बैठक का हिस्सा बनेंगे, जरूरत पड़ी तो ऑनलाइन बैठक से जुड़ेंगे। वहीं बैठक में भाग लेने के लिए ट्रस्टी युगपुरुष परमानंद और जगद्गुरु वासुदेवानंद सरस्वती अयोध्या पहुंच चुके हैं। ट्रस्ट के सदस्य डॉ. कृष्ण मोहन पहले से ही अयोध्या में मौजूद हैं। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समर्थन में लामबंदी भी तेज हो गई है। रविवार को राम कचहरी मंदिर में संत समाज ने प्रेस वार्ता कर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई। संतों ने कहा कि एसआईटी की जांच पूरी होने से पहले किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं है।

संक्षिप्त खबरें

फंदे पर डॉक्टर, पास मिली युवती की लाश

सहारनपुर। सहारनपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में किराए के कमरे से डॉक्टर और युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस के अनुसार कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. डॉक्टर का शव खिड़की से लटका मिला, जबकि युवती की लाश कमरे में पड़ी थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. थाना सदर बाजार क्षेत्र स्थित एसबीआई कॉलोनी के तिरंगा चौक के पास बुधवार देर रात एक किराए के कमरे से डॉक्टर और एक युवती के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर दोनों शवों को बाहर निकाला। मृतकों की पहचान केरल निवासी 39 वर्षीय सैम कमनीश और सहारनपुर के गागलहेड़ी क्षेत्र की रहने वाली 24 वर्षीय आस्था के रूप में हुई है। दोनों मृतकों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल और आपसी संपर्क की जानकारी जुटाई जा रही है।

सुल्तानपुरः हाईटेंशन लाइन टूटने से दो की मौत, जेई निलंबित

सुल्तानपुर। जिले के लंभुआ तहसील क्षेत्र के शंभूगंज बाजार में हाईटेंशन बिजली लाइन का जर्जर तार टूटने से दो लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद बिजली विभाग ने संबंधित अवर अभियंता (जेई) को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, बाजार में सड़क किनारे सब्जी बेच रहे सकवा गांव निवासी राधेश्याम यादव और गुरु प्रसाद गुप्ता अचानक टूटकर गिरे हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जर्जर बिजली तार को बदलने के लिए कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन विभाग ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता वी.के. जैन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित जेई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच के लिए विभागीय समिति गठित की गई है।

उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2026 का हुआ शानदार समापन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

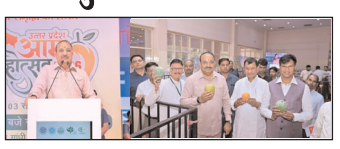

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ में चल रहे तीन दिवसीय 'उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2026' का रविवार को समापन हो गया। समापन दिवस पर मुख्य अतिथि प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने 180 से अधिक विजेताओं को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया। समापन दिवस पर उद्यान मंत्री ने आम की विभिन्न प्रजातियों की 07 श्रेणियों में एवं 56 वर्गों की प्रतियोगिता में 51 विजेताओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के कुल 147 पुरस्कार प्रदान किए। आम आधारित संरक्षित उत्पादों की प्रतियोगिता के 11 वर्गों के 19 विजेताओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के कुल 33 पुरस्कार तथा आम पकवान की प्रतियोगिता के 3 विजेताओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के कुल 3 पुरस्कार दिए गए। आम के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्श का पुरस्कार मोहम्मद इकबाल अहमद, प्रो. मेसर्स अवध नर्सरी, मलिहाबाद, लखनऊ को चौंसा प्रजाति के प्रदर्शन के लिए दिया गया। सर्वाधिक पुरस्कार विजेताओं में 20 पुरस्कार मोहम्मद इकबाल अहमद को, 17 पुरस्कार मोहम्मद अब्दुल सलीम, जैद नर्सरी, मलिहाबाद को तथा 14 पुरस्कार सुरेश चंद्र शुक्ला, गोमती नगर, लखनऊ को प्राप्त हुए। प्रदर्शनी में सर्वाधिक 190 प्रजातियों के प्रदर्शन हेतु सुरेश चंद्र शुक्ला को प्रथम, 92 प्रजातियों के प्रदर्शन हेतु उपेन्द्र सिंह, अवध आम उत्पादक सहकारी संघ, माल, लखनऊ को द्वितीय तथा 24 प्रजातियों के प्रदर्शन हेतु सूर्य मणि यादव, जौनपुर को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।08 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों की आम खाने की प्रतियोगिता में रुचिर शुक्ला पुत्र कर्नल रिषभी शुक्ला, लखनऊ को प्रथम, अरिक्ता सिंह पुत्री डॉ. धीरेन्द्र सिंह, लखनऊ को द्वितीय तथा दीपांशु यादव पुत्र रमेश कुमार यादव, बस्ती को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति का प्रथम स्थापना दिवस संपन्न

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति का प्रथम स्थापना दिवस शनिवार को लखनऊ में अत्यंत गरिमामय, भव्य एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में यह स्पष्ट संदेश गया कि संगठित पत्रकारिता ही लोकतंत्र की रीढ़ है। समारोह में पत्रकारिता, सामाजिक, धार्मिक एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अनेक गणमान्यजनों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजमोहन सिंह का ओजस्वी संबोधन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजमोहन सिंह ने अपने संबोधन में कहाः 'सम्मानित मंच, अध्यक्ष हरीश तिवारी, संयोजक राजेंद्र गुप्ता, महासचिव आशीष तिवारी और उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से आए पत्रकारिता के सच्चे सिपाही साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमस्कार। आज मुझे बेहद गर्व हो रहा है कि 'जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति' अपना पहला स्थापना दिवस मना रही है। साथियों, कलम और संविधान एक ही स्याही से चलते हैं। जिस दिन पत्रकार डर जाएगा, उस दिन लोकतंत्र भी डर जाएगा। जिस दिन पत्रकार बिक जाएगा, उस दिन सरकार भी बिक जाएगी। मैं एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष हूँ। रोज मेरी आलोचना भी होती है और तारीफ भी। लेकिन मैंने कभी किसी पत्रकार से ये नहीं कहा कि 'मेरे खिलाफ मत लिखो'। क्योंकि मैं जानता हूँ - आईना टूट सकता है, लेकिन सच नहीं टूटता।आज पत्रकार साथी सबसे ज्यादा परेशान हैं। मान्यता के नाम पर लटकाया जाता है, विज्ञापन के नाम पर दबाया जाता है, और सच लिखने पर धमकाया जाता है। भारतीय जन समाज पार्टी का वादा है। हम पत्रकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अंत में समिति के सभी पदाधिकारियों को दिल से बधाई। आपका पहला साल नींव का साल है, अगला साल इंकलाब का साल होगा।जय हिंद, जय संविधान, जय पत्रकारिता। धन्यवाद।' कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष हरीश तिवारी ने कहा कि 'उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति पत्रकारों के अधिकार, सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। हम संगठन को प्रदेश का सबसे मजबूत पत्रकार संगठन बनाएंगे।' समिति के महासचिव आशीष तिवारी ने प्रभावशाली मंच संचालन किया। वहीं कार्यक्रम के संयोजक राजेंद्र गुप्ता ने सभी अतिथियों का स्वागत कर उन्हें स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान समिति के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजमोहन सिंह को माला पहनाकर, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर ख्रुस्कके बांदा जिला अध्यक्ष राजेश कुमार यादव भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने पत्रकारों के सम्मान और लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते भारतीय जन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजमोहन सिंह समिति के पदाधिकारियों द्वारा अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

बिराहिमपुर ग्राम पंचायत की त्रिनेत्र योजना में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

शिकायतों और खबर प्रकाशित होने के बाद भी कार्रवाई नहीं

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मलिहाबाद, लखनऊ। मलिहाबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत बिराहिमपुर के मजरा रामपुर बस्ती में सरकार की महत्वाकांक्षी त्रिनेत्र योजना को लेकर गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान राम शंकर कश्यप ने ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से योजना में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी धन का दुरुपयोग किया। वहीं ग्राम पंचायत सचिव पर भी इस योजना में प्रधान के साथ मिलीभगत कर सरकारी धन हड़पने का आरोप है ग्रामीणों का कहना है कि इस पूरे मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई और समाचार भी प्रकाशित हुआ, लेकिन आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों के अनुसार, त्रिनेत्र योजना के तहत गांव में 16 ष्टष्टञ्जङ्क कैमरे लगाए गए। आरोप है कि इन कैमरों की खरीद और स्थापना के नाम पर करीब 2 लाख रुपये का भुगतान दिखाया गया, जबकि ग्रामीणों का दावा है कि बाजार में इन कैमरों की वास्तविक कीमत लगभग 35 से 40 हजार रुपये के बीच है। ऐसे में ग्रामीणों ने सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

महिलाओं की निजता पर सबसे बड़ा सवाल

ग्रामीणों का सबसे गंभीर आरोप यह है कि CCTV कैमरों का उपयोग गांव की सुरक्षा के बजाय महिलाओं और युवतियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रतिदिन रात के समय प्रधान के कुछ करीबी लोग CCTV की रिकॉर्डिंग देखते हैं, जबकि ऐसा कार्य केवल अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। यदि जांच में यह आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह महिलाओं की निजता, सम्मान और उनके मौलिक अधिकारों से जुड़ा अत्यंत गंभीर मामला होगा। ग्रामीणों का कहना है कि इस पूरे मामले की शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारियों से कई बार की गई और खबरें भी प्रकाशित हुईं, लेकिन आज तक किसी भी स्तर पर जांच शुरू नहीं की गई। उनका आरोप है कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण अधिकारी अब कार्रवाई से बच रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सवाल किया है कि क्या किसी ग्राम प्रधान, नेता या जनप्रतिनिधि का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद उसके कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच नहीं होगी? क्या सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप केवल समय बीत जाने से समाप्त हो जाते हैं, या फिर दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी? ग्रामीणों ने मांग की है कि त्रिनेत्र योजना के पूरे खर्च का तकनीकी एवं वित्तीय ऑडिट कराया जाए, CCTV कैमरों की खरीद से जुड़े सभी अभिलेखों की जांच की जाए, रिकॉर्डिंग तक किस-किस की पहुंच रही इसकी भी जांच हो और यदि किसी भी स्तर पर वित्तीय अनियमितता या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अब पूरा मामला प्रशासन की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई पर टिका है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस मामले में भी कार्रवाई नहीं हुई, तो सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े होंगे।

पीएम सूर्य घर योजना के बारे में दी जानकारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां (सीतापुर)। संविदा कर्मी परिजन सेवा संस्थान द्वारा गत दिवस बिसवां तहसील के गांव बुढ़नापुर (भिठमनी) में पी0एम0 सूर्य घर योजना अंतर्गत जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मोहसिन अंसारी ने किया ।मुख्य अतिथि कौशल कुमार ने उपस्थित दर्जनों ग्रामीणों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने योजना ग्रामीणों को योजना के लाभ, उसकी पात्रता, आवेदन करने की प्रक्रिया और सोलर रूफटॉप स्थापना सम्बन्धी जानकारी दी साथ ही उपस्थित लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिये गये और उनका समाधान प्रक्रिया भी समझायी गयी। अंत में व्यवस्थापक मो0 जुबेर ने सभी उपस्थित लोगों को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान वारिस अली, आशीष यादव, राकेश कुमार, मो0 जावेद,जसीम, करीमुल्ला, कौशल कुमार , मोहर्रम अली, इस्लाम खां,मो0 जुबेर खां,मो0 फैसला, आर्यन वर्मा, अबू सहमा खां, छोटे व दीपक यादव सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे।

श्रीलंका की जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प: 25 की मौत, 100 घायल

इस हिंसा के बाद श्रीलंकाई सेना को मदद के लिए बुलाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति को काबू करने के लिए सेना से समर्थन मांगा। यह झड़प रविवार को शुरू हुई थी, जब दोषी कैदियों और हिरासत में रखे गए कैदियों के बीच संघर्ष हुआ। यह घटना श्रीलंका के तटीय शहर नेगोम्बो की एक अधिक भीड़भाड़ वाली जेल में हुई। रॉयटर्स ने यह जानकारी सूत्रों के हवाले से दी है।स्थानीय टेलीविजन चैनल हिरू के अनुसार, मृतकों में कैदी और जेल अधिकारी दोनों शामिल हैं। यह जेल कोलंबो से करीब 35 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। झड़प किस कारण शुरू हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

लेकिन बताया जा रहा है कि सोमवार को हिंसक झड़प के दौरान कुछ कैदियों ने जेल के हथियार छीन लिए, जिसके बाद हिंसा और बढ़ गई और स्थिति घातक हो गई।रॉयटर्स ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि जेल के कुछ हिस्सों में अभी भी तलाशी और सफाई का काम चल रहा है और मृतकों व घायलों की सही संख्या का पता लगाया जा रहा है।

कोलंबो(एजेंसी)। श्रीलंका में सोमवार को कैदियों के बीच हुई हिंसक झड़प में 25 लोगों की मौत हो गई। करीब 100 लोग घायल हो गए। मृतकों में जेल अधिकारियों के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। इस हिंसा के बाद श्रीलंकाई सेना को मदद के लिए बुलाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति को काबू करने के लिए सेना से समर्थन मांगा। यह झड़प रविवार को शुरू हुई थी, जब दोषी कैदियों और हिरासत में रखे गए कैदियों के बीच संघर्ष हुआ। यह घटना श्रीलंका के तटीय शहर नेगोम्बो की एक अधिक भीड़भाड़ वाली जेल में हुई। रॉयटर्स ने यह जानकारी सूत्रों के हवाले से दी है।स्थानीय टेलीविजन चैनल हिरू के अनुसार, मृतकों में कैदी और जेल अधिकारी दोनों शामिल हैं। यह जेल कोलंबो से करीब 35 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। झड़प किस कारण शुरू हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

लेकिन बताया जा रहा है कि सोमवार को हिंसक झड़प के दौरान कुछ कैदियों ने जेल के हथियार छीन लिए, जिसके बाद हिंसा और बढ़ गई और स्थिति घातक हो गई।रॉयटर्स ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि जेल के कुछ हिस्सों में अभी भी तलाशी और सफाई का काम चल रहा है और मृतकों व घायलों की सही संख्या का पता लगाया जा रहा है। श्रीलंकाई सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर वारुणा गामागे ने बताया कि सेना को पुलिस की मदद के लिए बुलाया गया है। लेकिन फिलहाल वे तैयार स्थिति में हैं। डेराना समेत कई टेलीविजन चैनलों के वीडियो फुटेज में दिखाया गया कि एक पुलिस बस घायलों को ले जा रही है। कुछ घायल कैदी बस के फर्श पर पड़े हुए थे। जेल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी: अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली(एजेंसी)। भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को लेकर भारतीय रेलवे ने विशेष तैयारियां की हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रथ यात्रा के दौरान 300 से अधिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा केरल में ओणम त्योहार के लिए भी 100 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के साथ मिलकर ओडिशा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ की आगामी रथ यात्रा के लिए भारतीय रेलवे की तैयारियों का जायजा लिया। अश्विनी वैष्णव ने भीड़ प्रबंधन, यात्रियों की आवाजाही और ऑपरेशनल तैयारियों सहित रेलवे की व्यवस्थाओं का समग्र मूल्यांकन किया। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन ने उन्हें त्योहार के सुचारू संचालन के लिए की गई एकीकृत व्यवस्थाओं और विस्तृत ऑपरेशनल योजना के बारे में जानकारी दी। सीएम माझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ पवित्र शहर पुरी में नई 'पुरी-कोरापुट-पुरी' ट्रेन का उद्घाटन किया, जो श्रीक्षेत्र को शबर श्रीक्षेत्र से

सीधे जोड़ती है। तटीय, पश्चिमी और दक्षिणी ओडिशा को जोड़ने वाली यह नई ट्रेन जगन्नाथ भक्तों के लिए एक अनूठा उपहार है। इस शुभ अवसर पर भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए रेलवे की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। यात्रा में लाखों भक्तों की सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए, भारतीय रेलवे ने सैकड़ों विशेष ट्रेनें चलाने, बड़े होल्डिंग एरिया, खान-पान और अतिरिक्त टिकट काउंटर जैसी अपनी सेवाओं को मजबूत किया है। उन्होंने आगे लिखा कि पीएम मोदी के के नेतृत्व में राज्य में सालाना रेलवे बजट में काफी बढ़ोतरी हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व बदलाव हो रहा है। 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत, पुरी रेलवे स्टेशन को भी उसकी सांस्कृतिक भव्यता को ध्यान में रखते हुए विश्व-स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रभु के आशीर्वाद से, यह सर्वांगीण विकास और राज्य के सभी जिलों तक रेल कनेक्टिविटी हमें एक समृद्ध ओडिशा और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में और आगे ले जाएगी। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने एक्स पोस्ट में लिखा कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में निर्माणाधीन पुरी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टेशन परिसर में चल रहे विभिन्न विकास एवं आधुनिकीकरण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने, स्टेशन की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने तथा महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की पावन रथयात्रा सहित वर्षभर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया गया।

पात्रा ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए 300 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, ताकि देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा ज्यादा सुविधाजनक और आसान हो सके।

रोजाना शराब की एक ड्रिंक भी बढ़ा सकती है हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा

रोजाना सिर्फ एक शराब की ड्रिंक भी आपकी सेहत पर असर डाल सकती है। इससे व्यक्ति का ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ सकता है जो आगे चलकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बन सकता है। 'हाइपरटेंशन' (अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का एक जर्नल) में प्रकाशित इस स्टडी में अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के करीब 19,548 से ज्यादा लोगों के डेटा को शामिल किया गया। इन लोगों की सेहत को कई सालों तक ट्रैक किया गया ताकि यह समझा जा सके कि शराब पीने और ब्लड प्रेशर बढ़ने के बीच क्या संबंध है। शोधकर्ताओं ने पाया कि शराब की मात्रा और ब्लड प्रेशर के बीच एक सीधा संबंध है। जैसे-जैसे रोजाना शराब का सेवन बढ़ता है, वैसे-वैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर (दिल द्वारा शरीर में रक्त पंप करने का दबाव) में भी बढ़ोतरी होती है। अध्ययन के अनुसार, कम मात्रा में शराब पीने वाले लोगों में भी ब्लड प्रेशर में हल्की लेकिन लगातार वृद्धि दर्ज की गई। इसका मतलब यह है कि भले ही शुरुआती स्तर पर यह बदलाव बहुत बड़ा न लगे, लेकिन लंबे समय में यह हृदय और रक्त वाहिकाओं पर दबाव बढ़ा सकता है। यह

स्थिति आगे चलकर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अन्य हृदय संबंधी बीमारियों का कारण बन सकती है। इसके अलावा, अध्ययन में यह भी देखा गया कि पुरुषों में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर (जो दिल की धड़कनों के बीच रक्त वाहिकाओं में दबाव को मापता है) में वृद्धि हुई, जबकि महिलाओं में यह प्रभाव स्पष्ट रूप से नहीं देखा गया। यह निष्कर्ष मिरर की रिपोर्ट में भी सामने आया। अध्ययन के प्रमुख लेखक प्रोफेसर मार्को विंसेटी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मोडेना एंड रेजियो एमिलिया से जुड़े हैं और बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में एडजंक्ट प्रोफेसर भी हैं, ने कहा कि उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कम मात्रा में शराब का सेवन भी रक्तचाप में नकारात्मक बदलाव ला सकता है। उन्होंने कहा, 'हमें कम स्तर पर शराब पीने से कोई लाभकारी प्रभाव नहीं मिला, जब इसकी तुलना शराब न पीने वालों से की गई।' प्रोफेसर विंसेटी ने यह भी कहा कि शराब केवल ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि शराब का सेवन सीमित रखना चाहिए और यदि संभव हो तो इसे पूरी तरह से टालना और भी बेहतर है। ट्यूलाने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के प्रोफेसर पॉल व्हेलन, जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग के अध्यक्ष भी हैं, ने इस शोध की व्याख्या करते हुए कहा कि जिन प्रतिभागियों का शुरुआती ब्लड प्रेशर पहले से ही थोड़ा बढ़ा हुआ था, उनमें शराब के प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस के अनुसार, आम वयस्कों में उच्च रक्तचाप आमतौर पर 140/90 एमएमएचजी या उससे अधिक माना जाता है। अध्ययन में पाया गया कि लगभग 12 ग्राम शराब प्रतिदिन लेने वालों में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर औसतन 1.25 एमएमएचजी तक बढ़ गया। वहीं, जो लोग प्रतिदिन लगभग 48 ग्राम शराब का सेवन करते थे, उनमें ब्लड प्रेशर में औसतन 4.9 एमएमएचजी तक की वृद्धि देखी गई।

रहूं मैं तेरे रूबरू को लेकर संजय गुप्ता की टिप्पणी से छिड़ी बहस

'रहूं मैं तेरे रूबरू' का टीज़र रिलीज़ होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा हो रही है। दर्शकों ने टीज़र में दिखाए गए रोमांस, मिस्ट्री और सस्पेंस की तारीफ की है। वहीं फिल्म की नई स्टारकास्ट और अलग कहानी ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। लेकिन फिल्म की चर्चा के बीच एक ऐसा विवाद शुरू हो गया, जिसने पूरे मुद्दे को एक नई दिशा दे दी। यह फिल्म किसी बड़े सुपरस्टार, मशहूर फिल्म परिवार या बड़े बैनर की नहीं है। 'रहूं मैं तेरे रूबरू' के जरिए आर्या कुमार, नीता शेट्टी और पीहू बिस्वास जैसे नए कलाकार दर्शकों के सामने आ रहे हैं। इनके साथ पूरी टीम ने अपने सपनों और मेहनत के दम पर इस फिल्म को बनाया है। हर नए कलाकार और फिल्ममेकर की तरह इन्हें भी सिर्फ अपने काम के जरिए दर्शकों तक पहुंचने का एक मौका चाहिए। विवाद की शुरुआत तब हुई जब जाने-माने ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ङ्क पर फिल्म के टीज़र की तारीफ करते हुए पोस्ट शेयर की। तारण आदर्श वर्षों से छोटे-बड़े बजट और नए-पुराने सभी तरह की फिल्मों को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देते रहे हैं। उन्होंने भी इसी तरह इस फिल्म के टीज़र की सराहना की। इसके बाद निर्देशक संजय गुप्ता ने तारण आदर्श की उसी पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा– हालांकि संजय गुप्ता ने अपने पोस्ट में फिल्म का नाम नहीं लिया, लेकिन यह टिप्पणी तारण आदर्श की 'रहूं मैं तेरे रूबरू' वाले पोस्ट पर की गई थी। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे सीधे इस फिल्म और उसके प्रमोशन से जोड़कर देखा।

इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कई लोगों का मानना था कि इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणियां नई फिल्मों और नए कलाकारों का मनोबल गिराती हैं। लोगों

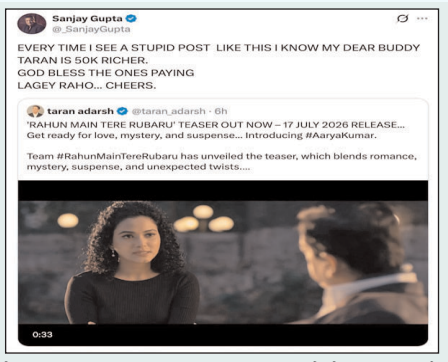

ने सवाल उठाया कि क्या बिना फिल्म देखे सिर्फ उसके प्रमोशन को लेकर इस तरह की बातें करना सही है? इस बीच वरिष्ठ पत्रकार उपाला केबीआर ने संजय गुप्ता की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि किसी वरिष्ठ ट्रेड एनालिस्ट पर इस तरह सार्वजनिक टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को केवल बड़े बजट की फिल्मों की नहीं, बल्कि छोटे और मिड-बजट की फिल्मों की भी जरूरत है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि नए निर्देशक, नए कलाकार और नई फिल्में भी प्रोत्साहन की हकदार हैं। हर बड़ा निर्देशक और अभिनेता कभी न कभी नया ही था। अगर शुरुआत में उन्हें मौका और समर्थन नहीं मिलता, तो वे आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते।

उपाला के इस जवाब को सोशल मीडिया पर काफी समर्थन मिला। कई लोगों ने कहा कि भारतीय सिनेमा हमेशा इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि यहां हर तरह की फिल्मों को जगह मिली। बड़े स्टार्स की फिल्मों के साथ-साथ छोटे बजट और नए फिल्मकारों की फिल्मों ने भी इंडस्ट्री को नई पहचान दी है। इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है–क्या नए कलाकारों और स्वतंत्र फिल्मकारों को दर्शकों के फैसले से पहले ही हतोत्साहित किया जाना चाहिए?स्वतंत्र फिल्मकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी फिल्म को लोगों तक पहुंचाना होती है। उनके पास न बड़े स्टार होते हैं, न भारी-भरकम मार्केटिंग बजट और न ही बड़े प्रोडक्शन हाउस का सहारा। ऐसे में किसी प्रतिष्ठित ट्रेड एनालिस्ट या पत्रकार का एक सकारात्मक पोस्ट उनकी फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। बाद में सोशल मीडिया पर बढ़ते विवाद और प्रतिक्रियाओं के बाद संजय गुप्ता ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक यह मामला सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स और नए फिल्मकारों को मिलने वाले अवसरों और सम्मान पर बड़ी बहस बन चुका था। 'रहूं मैं तेरे रूबरू' को एस. एस. एंटरटेनमेंट वर्ल्ड प्रस्तुत कर रहा है। फिल्म में आर्या कुमार, नीता शेट्टी और पीहू बिस्वास मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसका निर्देशन इंदर दास ने किया है, जबकि कहानी और स्क्रीनप्ले आर्या कुमार ने लिखा है। फिल्म की निर्माता सुमन सौरभ हैं। यह फिल्म 17 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। आखिरकार, हर फिल्म का फैसला दर्शकों को उसे देखने के बाद करना चाहिए, न कि रिलीज़ से पहले। चाहे फिल्म किसी बड़े बैनर की हो या किसी नए फिल्मकार की, हर किसी को अपने काम को निष्पक्ष तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने का समान अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि भारतीय सिनेमा का इतिहास गवाह है कि हर बड़ा सितारा और हर सफल फिल्मकार कभी न कभी एक नया चेहरा था, जिसके पास सिर्फ एक सपना और खुद को साबित करने का जुनून था।

एयरटेल नेटवर्क से वंचित निबिया के आसपास के आठ गांव, हजारों लोग परेशान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि। डिजिटल इंडिया के युग में जहां देश तेज़ 4G और 5G सेवाओं की ओर बढ़ रहा है, वहीं श्रीभूमि ज़िले के रामकृष्णनगर विधानसभा निबिया के आसपास क्षेत के कालामागुरा क्षेत्र के रांगपुर ग्राम पंचायत के आठ गांव आज भी मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सुविधा से वंचित हैं। दुर्गापुर, भीतरबालिया, विष्णुराम बस्ती, सर्माफा बस्ती, सातकरागेनाई, भड़बालिया, 4 नंबर भीतरबालिया और 5 नंबर बलिया गांवों के हजारों परिवार लंबे समय से खराब नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में केवल एक एयरटेल टावर मौजूद है, लेकिन उसकी क्षमता बेहद सीमित है और 4G/5G सेवाएं लगभग अनुपस्थित हैं। परिणाम

दुर्गापुर, भीतरबालिया, विष्णुराम बस्ती, सर्माफा बस्ती, सातकरागेनाई, भड़बालिया, 4 नंबर भीतरबालिया और 5 नंबर बलिया गांवों के हजारों परिवार लंबे समय से खराब नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में केवल एक एयरटेल टावर मौजूद है, लेकिन उसकी क्षमता बेहद सीमित है और 4G/5G सेवाएं लगभग अनुपस्थित हैं। परिणाम स्वरूप, मोबाइल नेटवर्क अक्सर बाधित रहता है और इंटरनेट सेवा लगभग ठप हो जाती है। इसका सीधा असर छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई, परीक्षा फॉर्म भरने, परिणाम देखने और अन्य शैक्षणिक कार्यों पर पड़ रहा है। इसके अलावा बैंकिंग सेवाएं, आधार से जुड़े कार्य, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और रोज़मर्रा के डिजिटल कामों के लिए ग्रामीणों को 10 से 12 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में भी बुनियादी मोबाइल नेटवर्क से वंचित रहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लंबे समय से समस्या बनी रहने के कारण हजारों लोग गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, स्थानीय विधायक विजय मालाकार तथा संबंधित प्रशासन से जल्द से जल्द नए मोबाइल टावर की स्थापना या मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन की मांग की है। ताकि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो सके।

रिश्वतखोरी के मामले में उत्तरी रेलवे के दो अधिकारियों समेत तीन गिरफ्तार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित रिश्वतखोरी के एक मामले में उत्तरी रेलवे के मुख्य सामग्री प्रबंधक (सीएमएम) और एक वरिष्ठ लिपिक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सीबीआई ने शुक्रवार रात रिश्वत के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद नई दिल्ली स्थित बड़ौदा हाउस में उत्तरी रेलवे मुख्यालय पर छापेमारी की थी। जांच एजेंसी ने मुख्य सामग्री प्रबंधक (स्टोर) नरेंद्र सिंह और वरिष्ठ लिपिक लेनिन शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा, 'आरोप है कि उत्तरी रेलवे मुख्यालय के ये लोक सेवक एक निजी कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मिलीभगत कर भ्रष्टाचार में शामिल थे। वे कथित तौर पर अवैध रिश्वत के बदले रेलवे के ठेके दिलाने में निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचा रहे थे।' प्रवक्ता ने कहा कि सार्वजनिक खरीद से जुड़े निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर ठेके दिए गए। सीबीआई के आधिकारिक बयान के अनुसार, 'ट्रैप कार्रवाई के दौरान निजी कंपनी के प्रतिनिधि शारिक अली द्वारा उत्तरी रेलवे के मुख्य सामग्री प्रबंधक को दी गई एक लाख रुपये की रिश्वत की राशि बरामद की गई।' अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने दोनों सरकारी अधिकारियों और कथित रिश्वत देने वाले शारिक अली को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर और कानपुर स्थित विभिन्न ठिकानों पर तलाशी ली गई, जहां से कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद हुए हैं। सीबीआई ने इस मामले में उत्तरी रेलवे मुख्यालय, बड़ौदा हाउस में तैनात मुख्य सामग्री प्रबंधक नरेंद्र सिंह, उप मुख्य सामग्री प्रबंधक शुभाशीष मैती और वरिष्ठ लिपिक (स्टोर) लेनिन शर्मा को आरोपी बनाया है। प्राथमिकी में उत्तर प्रदेश के कानपुर के जाजमऊ स्थित मैश इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (मैश एंड कंपनी) के कारोबारी शारिक अली और एजाज अली के नाम भी शामिल हैं। कंपनी को भी आरोपी बनाया गया है। एफआईआर के अनुसार, शारिक अली कथित तौर पर लेनिन शर्मा और उनके सहयोगियों के माध्यम से रेलवे टेंडरों से जुड़ी 'महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारी' तथा अन्य लाभ अवैध रिश्वत के बदले नियमित रूप से हासिल करता था।

जमीन तक तय नहीं हुई, लेकिन कागज़ों में छह साल से चल रहा 100 बेड का अस्पताल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। मध्य प्रदेश के इंदौर के खजराना इलाके में प्रस्तावित 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल को लेकर एक अजीब प्रशासनिक स्थिति सामने आई है. यह अस्पताल पिछले छह वर्षों से सरकारी रिकॉर्ड में पूरी तरह 'संचालित' माना जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि अब तक उसकी एक भी ईंट नहीं रखी गई है. यहां तक कि अस्पताल के लिए जमीन का अंतिम चयन भी नहीं हो पाया है। छह साल पहले (साल 2020 में) मध्य प्रदेश सरकार ने खजराना में एक आधुनिक सिविल अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की थी. लेकिन अस्पताल के लिए उपयुक्त जमीन की तलाश लंबी खिंचती चली गई. इसके बावजूद प्रशासनिक प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती रही. स्वास्थ्य विभाग ने इस अस्तित्वहीन अस्पताल के लिए डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मचारियों सहित 87 पदों को मंजूरी दे दी। इसके बाद वर्षों तक नियमित रूप से इन पदों पर नियुक्तियां और तबादले किए जाते रहे. अस्पताल का भवन नहीं होने के कारण इन कर्मचारियों को शहर के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों, जिनमें हुकुमचंद अस्पताल, पीसी सेठी अस्पताल और अन्य सरकारी चिकित्सा संस्थान शामिल हैं, में तैनात किया जाता रहा। इस असामान्य स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने परियोजना का इतिहास बताते हुए कहा, 'शुरुआत में यहां एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित होता था।

बाद में इसे 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में उन्नत किया गया और फिर इसे 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई। उन्होंने कहा कि उपयुक्त सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण अस्पताल का निर्माण शुरू नहीं हो सका. 'जब तक अस्पताल की इमारत तैयार नहीं हो जाती, तब तक स्वीकृत कर्मचारियों को अन्य सरकारी चिकित्सा संस्थानों में तैनात किया गया है. जमीन की तलाश अभी भी जारी है.' इस बीच, इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव हसानी ने निर्माण में हुई देरी की वजह बताते हुए कहा, 'शहर की सीमा के भीतर इतनी बड़ी सरकारी जमीन उपलब्ध कराना आसान नहीं है. यही कारण है कि अस्पताल का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि अस्पताल के लिए स्वीकृत नर्सिंग और पैरामेडिकल कर्मचारियों को संजीवनी क्लीनिकों और अन्य सरकारी अस्पतालों से संबद्ध कर दिया गया है, ताकि उनकी सेवाओं और कौशल का प्रभावी उपयोग किया जा सके।

वी-केयर अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने छात्राओं को सुरक्षा का दिया मंत्र

आत्मरक्षा से साइबर सुरक्षा तक किया जागरूक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'बाल सुरक्षा जागरूकता माह' के अंतर्गत 'वी-केयर' अभियान के तहत सोमवार को ज्वालापुरी स्थित सीएम श्री स्कूल, अमलवास में छात्राओं के लिए विशेष सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को व्यक्तिगत सुरक्षा, आत्मरक्षा, सड़क सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक बनाना तथा उनमें आत्मविश्वास विकसित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली पुलिस के वाद्यवृंद (ऑर्केस्ट्रा) दल द्वारा देशभक्ति गीतों की मनमोहक प्रस्तुति से हुई। गीतों ने छात्राओं का मन मोह लिया और पूरे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल बना दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की विभिन्न

इकाइयों ने सुरक्षा से जुड़े विषयों पर जागरूकता सत्र आयोजित किए।महिला एवं बाल सुरक्षा प्रकोष्ठ एसपीयूडब्ल्यूएसी की टीम ने छात्राओं को आत्मरक्षा का महत्व समझाया और विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की सुरक्षा के लिए आवश्यक आत्मरक्षा के गुर सिखाए। टीम ने कई तकनीकों का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया, जिससे छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ा।यातायात पुलिस की टीम ने छात्राओं को सड़क पर सुरक्षित चलने, यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित आवागमन के बारे में जानकारी दी। इस दौरान यातायात जागरूकता वाहन के माध्यम से सड़क सुरक्षा से संबंधित शिक्षाप्रद चलचित्र भी दिखाए गए।बाहरी जिले के साइबर थाना के अधिकारियों ने छात्राओं को ऑनलाइन ठगी, डिजिटल धोखाधड़ी, फर्जी लिंक, साइबर अपराध और सामाजिक माध्यमों के सुरक्षित उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही इंटरनेट का सावधानी और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने की सलाह भी दी।कार्यक्रम स्थल पर दिल्ली पुलिस का जनसंपर्क वाहन भी मौजूद रहा, जिसमें बाल सुरक्षा से जुड़े जागरूकता वीडियो प्रदर्शित किए गए। इन वीडियो के माध्यम से छात्राओं को सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण संदेश सरल और प्रभावी ढंग से समझाए गए।कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए सुरक्षा विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके अलावा रस्साकशी प्रतियोगिता भी कराई गई, जिससे छात्राओं में टीम भावना और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा मिला।इस कार्यक्रम में विद्यालय की 200 से अधिक छात्राओं, शिक्षकों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिला एवं बाल सुरक्षा प्रकोष्ठ की पुलिस उपायुक्त नेहा यादव (आईपीएस) ने कहा कि वी-केयर अभियान के माध्यम से दिल्ली पुलिस बच्चों विशेषकर छात्राओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ-साथ समाज और पुलिस के बीच विश्वास को भी मजबूत करते हैं।